

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

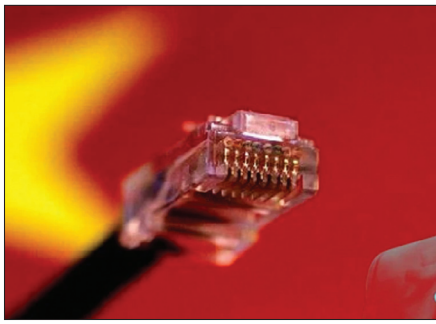
महाराष्ट्र में अकेली पड़ी कांग्रेस

शिवसेना, एनसीपी में चौंकाते वाली टूट के बाद अब अगली बड़ी टूट क्या कांग्रेस में होगी? इस सवाल का जवाब सरकारात्मक है। बहुत संभव है कि अब महाराष्ट्र कांग्रेस में भी बिखराव आ जाए। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता अजित पवार के पाला बदल कर सरकार में उपमुख्यमंत्री बन जाने के अत्यंत आश्चर्यजनक राजनीतिक घटनाक्रम को कांग्रेस में काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। पार्टी के बड़े नेता भी मान रहे हैं कि अजित पवार के बीजेपी के साथ चले जाने के बाद अगले साल होनेवाले चुनाव में हार-जीत का गणित बदल चुका है और इस कारण कांग्रेस विधायकों के लिए भी पालाबदल करके सत्ता के साथ जाने का रास्ता खुल गया है। सतर्कता यह बरती जा रही है कि किसी को खबर तक नहीं लगे कि किस पर नजर रखी जा रही है और सावधानी यह भी कि पार्टी को लगातार एकजुट बनाए रखना है। खास ध्यान इस पर है कि कांग्रेस का कौनसा विधायक बीजेपी के किस बड़े नेता के संपर्क में है, किस विधायक पर किस बीजेपी नेता का प्रभाव है तथा कौन कौन से विधायक हार के गणित से डर कर किसी दूसरे रास्ते पर अपने कदम बढ़ा सकते हैं, इसका गहन आकलन किया जा रहा है। जानकारी इस बात की भी जुटाई जा रही है कि अजित पवार किस कांग्रेस नेता को अपने साथ लाने में सक्षम साबित हो सकते हैं। कांग्रेस में हालात सावधानी के हैं। दिल्ली में बैठे आलाकमान सतर्क हैं, और महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक सहमे हुए हैं क्योंकि सब के सब स्कैन पर हैं। फोन पर किसी से खुलकर बात करना भी उनको नहीं सुहा रहा। महाराष्ट्र में कांग्रेस की नजर अब अपने ही विधायकों पर इसलिए है, क्योंकि आलाकमान को पता है कि पार्टी में प्रादेशिक नेताओं के बीच व्यक्तिगत स्तर पर काफी खींचतान है। विधायकों में असंतोष भी है। कांग्रेस नेतृत्व इस तथ्य से भी बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ है कि एनसीपी में बड़ी टूट से प्रदेश के बदले हुए राजनीतिक हालात में कांग्रेस विधायकों को हार की चिंता सता रही है। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों के लिए अगला चुनाव जीतना मुश्किल होगा। ऐसे में हर विधायक सुरक्षित रास्ता अपनाना चाहता है। कांग्रेस विधायकों के लिए अब भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से दूरी बनाकर रखना कोई बड़ा कारण नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पहले भी कट्टर हिंदुत्व की विचार रखने वाली शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में सहभागी रही है। इस कारण से ही कांग्रेस के विधायकों के लिए शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सामूहिक सरकार के साथ खड़े रहना ज्यादा आसान है। वैचारिक रूप से भी कांग्रेस सदा से राष्ट्रवादी कांग्रेस की सबसे करीबी पार्टी रही है। नई दिल्ली की नजर मुंबई पर इसी कारण है, क्योंकि उसे अपने विधायकों को साथ रखे रहना ज्यादा जरूरी हो गया है। हालात कांग्रेस में टूट के समर्थन में हैं और माहौल भी।

विरोध में भारत नहीं था अकेला, इस मुस्लिम देश ने भी दिया पीएम मोदी का साथ

चीनी बीआरआई को भारत का समर्थन नहीं

नई दिल्ली। बीआरआई प्रोजेक्ट की वजह से ही दुनिया के कई देश चीन के कर्जजाल में फंसकर कंगाल हो चुके हैं। भारत ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने से साफ इनकार कर दिया। शिखर सम्मेलन के अंत में जारी नई दिल्ली घोषणा में भारत ने बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव (बीआरआई) का समर्थन करने वाले पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। समिट के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने महत्वकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का जिक्र किया। लेकिन इसे कोई ज्यादा तवज्जो नहीं मिल सकी। जिनपिंग की तरफ से बीआरआई की बात को रखने के बावजूद भारत ने इसे नजरअंदाज किया। लेकिन साइथ चाइना मॉनिंग पोस्ट की खबर के अनुसार भारत के अलावा ईरान की तरफ से भी जिनपिंग की बात से ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई।



देश उसके कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। चीन के प्रोजेक्ट पर भारत हमेशा से खुलकर ऐतराज जताता रहा है। ऐतराज की वजह है ये कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से गुजरता है जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है।

भारत नहीं करेगा समर्थन

जिनपिंग ने समिट के दौरान कहा कि बीआरआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार और निवेश को आसान बनाएगा। इसके साथ ही बीआरआई में बेहतर तालमेल की अपील की। इसके बाद जो साझा बयान जारी किया गया उससे पता लगता है कि भारत और ईरान ने जिनपिंग की बीआरआई नीति का समर्थन नहीं किया है। भारत ने चीन की महत्वकांक्षी 'बेल्ट एंड रोड' परियोजना (बीआरआई) का एक बार फिर समर्थन करने से इनकार कर दिया। इसी के साथ वह इस परियोजना का समर्थन नहीं करने वाला शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का एकमात्र देश बन गया। एससीओ शिखर सम्मेलन के अंत में जारी घोषणा में कहा गया कि रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने बीआरआई के प्रति अपना समर्थन दोहराया है।

क्या है बीआरआई

ईरान के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में तो सब जानते हैं। जिसके तहत वो सीपीईसी का निर्माण कर रहा है। इसके प्रोजेक्ट के जरिए चीन ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते यूरोप तक जाने का प्लान बनाया है। बीआरआई के जरिए चीन दुनिया के गरीब देशों को कर्ज दे रहा है और फिर उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहा है। अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक कई

देश उसके कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। चीन के प्रोजेक्ट पर भारत हमेशा से खुलकर ऐतराज जताता रहा है। ऐतराज की वजह है ये कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से गुजरता है जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है।

चीन ने दुनिया में किए सबसे अधिक साइबर हमले

साल 2013 यानी वो वर्ष जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) पहल की घोषणा की। जिसके बाद चीन ने कई पहल शुरू की हैं। 8 सितंबर 2020 को बीजिंग ने डेटा सुरक्षा पर वैश्विक पहल शुरू की। सितंबर 2021 में वैश्विक विकास पहल का अनावरण किया गया। अप्रैल 2022 में शी ने एशिया के लिए बोआओ फोरम के दौरान वैश्विक सुरक्षा पहल की घोषणा की। इस साल 16 मार्च को चीन ने वैश्विक सभ्यता पहल शुरू की। जिनपिंग की वन बेल्ट वन रोड ने काफी और परियोजनाओं के मुकाबले काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोरी है। इसके वनस्पद जोआईडीएस पर सबसे कम ध्यान दिया गया। इसका श्रेय चीन द्वारा इस पर खर्च किए गए तुलनात्मक रूप से कम प्रयास को दिया जा सकता है। लेकिन चीन पर नजर रखने वाले इस बात से सहमत होंगे कि बीजिंग एक बार वहां कुछ कर देता है, तो वह हमेशा के लिए होता है। इसका एक उदाहरण द्वितीय द्वीप श्रृंखला पर चीन का दावा है।

इनफॉर्मेशन वॉरफेयर में चीन आगे

दूसरे देशों की सीमाओं में घुसपैठ, अपनी महत्वकांक्षी परियोजनाओं के सहारे मदद लेने वाले देशों की जमीन पर कब्जा और विस्तरवाद के अलावा चीन अपने साइबर अटैक के लिए भी काफी फेमस है। हाल ही में खबर आई थी कि दुनिया भर में सर्वर डाउन होने और डेटा चोरी होने व साइबर फ्राड की वजह चीन है। वो पूरी दुनिया में हैकरों से साइबर हमले करवा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में ये दावा किया गया था। हालांकि चीन ने अमेरिकी रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। वहीं चीनी साइबर घुसपैठ की स्ट्रैटिक चेंज को लेकर भी एक थ्योरी सामने आई है। 25 मई को ऑस्ट्रेलिया और फाइव आइज इंटेलिजेंस-शेयरिंग नेटवर्क में उसके साझेदारों-कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस-ने %बोल्ड टाइफून% नामक साइबर हैकिंग समूह का खुलासा किया। समूह को 2021 से महत्वपूर्ण इनफॉर्मेशन में घुसपैठ करते हुए पाया गया है, लेकिन इसके व्यवहार पर हालिया खुफिया जानकारी चीनी साइबर प्रतिष्ठान में चिंताजनक विकास का संकेत देती है। फाइव आइज का खुलासा प्रत्यक्ष रूप से वोल्ड टाइफून के लिए चीनी सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। खतरे की वास्तविक प्रकृति और निहितार्थ को उजागर करने के लिए कई परतें हैं जिन्हें सामने लाने की जरूरत है।

चीन से उभरने वाले स्टेट इंफॉर्मर साइबर थ्रेट को दो व्यापक सरकारी संरचनाओं राज्य सुरक्षा मंत्रालय और सामरिक सहायता बल के तहत समूहीकृत किया जा सकता है। किसी भी देश की खुफिया एजेंसियां जाहिर तौर पर सीक्रेट रहती हैं। लेकिन चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटे सिक्वोरिटी यानी एमएसएस अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। न तो इसकी कोई आधिकारिक वेबसाइट है और न कोई संपर्कों की लिस्ट और न कोई प्रवक्ता। साल 1983 में स्थापित की गई एमएसएस काउंटर-इंटेलिजेंस, विदेशी इंटेलिजेंस, फ्रेलू सर्विलांस और नैशनल सिक्वोरिटी के लिए इंटेलिजेंस के काम करती है।

पीएम मोदी आज रायपुर में, आमसभा को करेंगे संबोधित

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर आएंगे, ये उनका 2018 के बाद पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ इसकी तैयारी में जुट गए हैं और बीजेपी दावा कर रही है कि डेढ़ लाख लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए आएंगे। भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के आने-जाने के लिए रूट मैप जारी किया है। इसके अलावा, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए 2 हजार जवानों की तैनात कर रही है।

दरअसल, 7 जुलाई को सुबह 10.45

मोदी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में पीएम रायपुर साइंस कॉलेज मैदान जाएंगे। जहां एक बड़ी आम सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इससे पहले 7500 करोड़ की सौगात पीएम मोदी छत्तीसगढ़ को देंगे। इसके लिए साइंस कॉलेज ग्राउंड में शासकीय कार्यक्रम के लिए भी एक मंच बनाया गया है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में करीब 2 घंटा का समय बिताएंगे। साइंस कॉलेज ग्राउंड में एक एमरजेंसी



हेलीपैड बनाया गया है। इस हेलीपैड में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की प्रैक्टिस को गई है। इसके अलावा मुख्य मंच के सामने 3 बड़े बड़े डोम खड़े किए गए हैं। जोकि पूरी तरह से वॉटर प्रूफ है। भीषण गर्मी हो या तेज बारिश से निपटने की क्षमता वाला है। मंच से डोम के बीच की दूरी 50 फीट रखी गई है। पूरे मंच को एस्पॉजी सुरक्षा रहेगी। मुख्य मंच पीएमओ के प्रोटोकॉल के हिसाब से ही तैयार किया जा रहा है, जोकि आज रात तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।

गोरखपुर से दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार राज्यों की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान 50,000 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक, पीएम मोदी शुक्रवार को गोरखपुर जाएंगे।



समान नागरिक संहिता की ओर बड़ा कदम, मंत्रियों को दी जिम्मेदारी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समान नागरिक संहिता की आवश्यकता के बारे में बोलने के एक सप्ताह बाद, इस मुद्दे पर आगे विचार-विमर्श के लिए मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) गठित किया गया है। सूत्रों ने बताया कि पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू की अध्यक्षता वाले जीओएम ने यूसीसी मुद्दे पर अपना परामर्श शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ अन्य सदस्य महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, ??कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्वोत्तर के प्रभारी मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बुधवार को भी जीओएम की मेरठन बैठक हुई। सूत्रों ने कहा कि पिछले दो दिनों में उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की गई है। मेघालय के सीएम कोनार्ड सांगा ने बुधवार को किरण रिजिजू से मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने ट्वीट किया- आज दोपहर अपने मित्र और माननीय मंत्री किरेन रिजिजू जी से मुलाकात करके खुशी हुई। हमने अपने लोगों के विकास और कल्याण से संबंधित सामान्य मुद्दों और एजेंडे पर विस्तृत चर्चा की। जानकारी के मुताबिक अलग-अलग मंत्री अलग-अलग मुद्दों पर विचार करेंगे।

कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने बनाया एनएसयूआई प्रभार

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को तत्काल प्रभाव से कन्हैया कुमार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) का प्रभारी नियुक्त किया। कांग्रेस महासचिव केशी वेणुगोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कन्हैया कुमार को तत्काल प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) का एआईसीसी प्रभारी नियुक्त किया है। कन्हैया कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) छोड़ने के बाद 2021 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वह तब से बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले, 2015-16 में, कुमार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते हुए, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे। इससे पहले, रूचि गुप्ता एनएसयूआई की प्रभारी थी जिन्होंने करीब ढाई साल पहले पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस की युवा शाखा के अध्यक्ष के रूप में कन्हैया कुमार को नियुक्त करने का निर्णय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को कड़ी चुनौती देने के पार्टी के प्रयास के तहत लिया गया है।

पश्चिम बंगाल में जबरन धर्म परिवर्तन मामले में एक्शन

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपी सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि एफआईआर कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत दर्ज की गई है। हाईकोर्ट ने दो बहनों की रिट याचिका के बाद जांच का आदेश दिया। दोनों बहनों ने यह दावा करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि मालदा जिले के कालियाचक इलाके के निवासी उनके पतियों को विधायक चुनाव हारने वाली एक राजनीतिक पार्टी के लिए काम करने की सजा के तौर पर बलपूर्वक हिंदू धर्म से जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि उनके पति 24 नवंबर, 2021 से लापता हैं, लेकिन पुलिस ने सूचना दिए जाने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि दोनों भाइयों ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म अपना लिया था और परिवारिक विवाद के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर, सीबीआई ने 20 फरवरी को प्रारंभिक जांच दर्ज की।

ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने इस साल मार गिराए 27 आतंकी

श्रीनगर। सेना के साथ संयुक्त अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इस साल अब तक जम्मू-कश्मीर में 27 आतंकवादियों को मार गिराया है। सीआरपीएफ ने बताया कि सूची में आठ स्थानीय और 19 विदेशी आतंकवादी शामिल हैं जिन्हें इस साल 5 जुलाई तक कश्मीर में मार गिराया गया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वर्ष 2022 में घाटी में सुरक्षा बलों ने कुल 187 आतंकवादियों को मार गिराया जिनमें 130 स्थानीय और 57 विदेशी आतंकवादी शामिल थे। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले वर्षों से तुलना करें तो घाटी में विदेशी आतंकवादियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। यह भी बताया कि इस साल विभिन्न अभियानों में 16 नक्सली पकड़े गए हैं। 23 जून को कुपवाड़ा के मांचिखल सेक्टर के काला जंगल में संयुक्त ऑपरेशन में चार आतंकियों को मार गिराया गया था। दरअसल, नए जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र अब देश के बेहतर स्थानों में शुमार हो रहा है। केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं।

एनडीए की बैठक में भाजपा के पूर्व सहयोगी ले सकते हैं हिस्सा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में सिर्फ आठ महीने बचे हैं, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 18 जुलाई को एक बैठक बुलाई है, जिसमें पूर्व सहयोगी शिअद, तेदेपा और एलजेपी (चिराग पासवान गुट) के शामिल होने की संभावना है। शिअद के सुखबीर बादल और चिराग पासवान ने बैठक के लिए अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है, जो नई दिल्ली के अशोका होटल में होगी। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनके साथ बैठक की। महाराष्ट्र में अजित पवार की बगावत और एनसीपी के एक धड़े के सरकार में शामिल होने के बाद कर्नाटक में जनता दल (सेक्युलर) और आंध्र प्रदेश में वॉईएसआरसीपी के साथ भाजपा के संभावित गठबंधन की सुगुवागट चल रही है। गुरुवार को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने राजनीतिक हलकों में इस चर्चा के बीच अपनी पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक की कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिअद और भाजपा फिर से एक हो सकते हैं। हालांकि, जब एसएडी की एनडीए में फिर से शामिल होने की योजना के बारे में पूछा गया तो बादल ने कहा कि यह एक निर्यात बैठक थी और पुनर्मिलन का कोई सवाल ही नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारा बसपा के साथ गठबंधन है।

विपक्ष को क्यों है जल्द चुनाव की आशंका?

लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में अटकलें लग रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच विधानसभा चुनावों के साथ ही हरियाणा और महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव और लोकसभा चुनाव करवाने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं की इस आशंका का कारण यह है कि भाजपा नेताओं की गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका और मिन्न दौरे से लौटने के बाद कुछ ज्यादा ही सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो चुका है, 28 जून को उन्होंने पार्टी संघटन और अपने मंत्रियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर कई बैठकें कीं। इन सभी बैठकों में अमित शाह भी मौजूद थे, जो भाजपा के चुनावी रणनीतिकार हैं। कुछ बैठकों में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। पिछले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के विभिन्न राज्यों में दौरे और रैलियां भी

बढ़ गई हैं, जो दर्शाती हैं कि भाजपा की चुनाव मशीनरी सक्रिय हो गई है। अगर यह सक्रियता सिर्फ चुनावी राज्यों में होती तो विपक्ष को ऐसा अंदेशा नहीं होता, लेकिन भाजपा के नेताओं के दौरे बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बढ़ गए हैं। इधर पिछले कुछ दिनों से केन्द्रीय मंत्रियों के भाजपा मुख्यालय में दौरे भी बढ़ गए हैं। वित्त मंत्री सीतारामण, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखो तो अक्सर पार्टी कार्यालय में आती रहती हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ऐसे ऐसे मंत्री भाजपा कार्यालय में दिखाई दिए, जिन्हें कभी पहले देखा नहीं गया था। अब इसमें विश्व हिन्दू परिषद की ओर से 9 जुलाई को अयोध्या में बन रहे श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर में दिल्ली से मीडिया को ले जाना जाना भी जुड़ गया है। विपक्ष के नेताओं के दिमाग में जल्द चुनाव की आशंका मोदी विरोधी यूट्यूब चैनलों ने डाली है, जिन्होंने जून के शुरू में ही जल्द चुनावों की आशंका व्यक्त करते हुए



रिटायर्ड पत्रकारों के साथ डिस्कशन शुरू कर दिया था। उनकी आशंका का एक आधार यह भी होता था कि भाजपा राहुल गांधी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है, इसलिए वह जल्द चुनाव करवा देना चाहती है, ताकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल तैयारियां न कर सकें। इसके बाद 14 जून को नीतीश कुमार ने दिसंबर में चुनाव करवाने की आशंका व्यक्त की थी, जब उन्होंने बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग पेंडिंग कामों को जल्दी निपटाईए क्योंकि यह जरूरी नहीं कि लोकसभा चुनाव 2024 में हों, इस साल दिसंबर में भी हो सकते हैं। कांग्रेस ने नीतीश

कुमार के जरिए इस आशंका को मोदी विरोधी विपक्षी दलों को डराने के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि उन्हें जल्द बातचीत की टेबल पर लाया जा सके। क्योंकि कुछ विपक्षी दलों के इंकार करने के कारण 12 जून को बैठक टल गई थी। 23 जून को हुई बैठक में भी जल्द चुनाव की आशंका व्यक्त की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की हार के बाद 5 विधानसभाओं के चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव करवा सकते हैं, ताकि इन विधानसभाओं में मोदी फेक्टर का लाभ उठाया जा सके। पांच जुलाई को जब राष्ट्रवादी कांग्रेस टूट रही थी, तब शरद पवार के पोते रोहित पवार ने तो यह दावे के साथ कहा कि लोकसभा चुनाव दिसंबर में हो जाएंगे। भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों की यही समस्या है कि वह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को नहीं समझते। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा हमेशा चुनावी राजनीति बनाने में

लगी रहती है। जबसे नरेंद्र मोदी ने केन्द्रीय राजनीति में कदम रखा है, भाजपा 24 घंटे सक्रिय रहने वाली पार्टी बन गई है। प्रवास और बैठक भाजपा की डिक्शनरी के प्रमुख शब्द हैं। अगर किसी भी अन्य राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इतने दौरे नहीं देखते होंगे, जितने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे होते हैं। भाजपा के संगठन मंत्रियों के हर महीने दौरे तय होते हैं। दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस में प्रादेशिक नेताओं को दिल्ली तलब किया जाता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता अगर कहीं दौरे करते भी हैं तो वहां विभिन्न स्तर की बैठकें नहीं होती, जैसी भाजपा के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी करते हैं। भाजपा की देखादेखी कांग्रेस ने भी संगठन महामंत्री का पद सृजित किया है, लेकिन कांग्रेस का संगठन महामंत्री हमेशा राहुल गांधी के साथ ही दौरे पर रहता है। इसके बावजूद कांग्रेस ने पदों के पीछे अन्य

विपक्षी दलों के प्रभाव वाले राज्यों में 25 प्रतिशत सीटों की मांग करना शुरू कर दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 80 में से 20 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 42 में से 10 सीटें छोड़ें, बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव 40 में से दस सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ें। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव तो कांग्रेस को 10 सीटें देने को तैयार हैं, लेकिन ममता बनर्जी और अखिलेश यादव बिलकुल तैयार नहीं हैं। ममता बनर्जी अब बंगाल में कांग्रेस के लिए दस सीटें छोड़ भी दें, तो भी भाजपा के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां प्रमुख विपक्षी दल सीपीएम के लिए ममता बनर्जी एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि 23 जून की बैठक में ममता के साथ साथ सीपीएम और सीपीआई के नेता भी मौजूद थे। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी केरल में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहती।

नक्सलियों पर नकेल, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर से दो गिरफ्तार

लेकर जा रहे थे मोटी रकम; एक का कांग्रेस से कनेक्शन

कांकेर। कांकेर जिले की सीमा से सटे महाराष्ट्र की गढ़चिरोली पुलिस ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सलियों को बड़ी रकम के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सल सहयोगियों में एक कांकेर जिले के पखाजुर क्षेत्र का रहने वाला 24 साल का युवक है। जो कि कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी का सदस्य बताया जा रहा है।

गुप्त सूचना पर पुलिस ने नगदी के साथ एकड़

गढ़चिरोली पुलिस की एक विशेष टीम को सूचना मिली थी कि दो युवक भारी मात्रा में नगदी रकम लेकर बाइक से आ रहे हैं। जिस पर पुलिस की स्पेशल टीम ने अहरी के पास नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी। इस दौरान बाइक से पहुंचे दो युवक रोहित मंगू और विप्लव सिकदार को पुलिस ने रोका और उनके बैग की तलाशी ली तो उसमें दो हजार के नोट समेत 27 लाख से अधिक रकम बरामद हुई।



पुलिस कर रही नक्सलियों से पूछताछ

लेकर पूछताछ की तो दोनों ही इतनी बड़ी रकम को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गढ़चिरोली पुलिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह रकम नक्सलियों की है, 27 लाख 62 हजार में से 12 लाख रुपये के नोट दो हजार के नोट हैं। जिसे बदलने के लिए ले जाया जा रहा था।

नक्सलियों ने की थी ग्रामीण की हत्या

कांकेर। जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जुंगड़ा में एक ग्रामीण की हत्या की जिम्मेदारी अब नक्सलियों ने ली है। माओवादियों ने एक बैनर लगाकर हत्याकांड को स्वीकार किया है। ज्ञात हो कि नक्सलियों ने 26 जून को ग्राम जुंगड़ा निवासी सनहू राम गोटा की हत्या कर उसकी लाश सड़क पर फेंक दी थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी थी। पुलिस ने मार्ग कायम कर मामला जांच में लिया था। इसी बीच अब नक्सलियों ने एक बैनर कोयलीबेड़ा-आलपरस मार्ग में टांग कर इस बात की पुष्टि की है कि ग्रामीण सनहू राम की हत्या उन्होंने की है। नक्सलियों ने बकायदा इसका कारण स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मृतक के ऊपर मुखबीरी करने का शक था, नक्सलियों को आशंका है कि सनहू राम गोटा माओवादियों की सूचना पुलिस तक पहुंचाता था। इसके चलते ही उसकी हत्या कर दी गई है। उन्होंने बैनर में यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई और ग्रामीण भी इसी तरह मुखबीरी करता पाया गया तो उसका अंजाम भी यही होगा।

चिटफंड कंपनी के निवेशकों को धनराशि वापस दिलाने जिला प्रशासन सतत् प्रयासरत

ठगी करने वाले कंपनियों की सम्पत्ति कुर्क कर निवेशकों को वापस की जा रही धनराशि

कोरबा। प्रदेश सरकार की मंशानुसार जिले में चिटफंड कंपनी के निवेशकों की धनराशि वापस दिलाने हेतु जिला प्रशासन सतत् प्रयासरत है। ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्रवाई एवं उनकी सम्पत्तियों को कुर्क कर निवेशकों को राशि वापस की जा रही है। कोरबा तहसील के ग्राम कोरबा में बी. एन. गोल्ड रियल स्टेट एण्ड एलाइड लिमिटेड की पटवारी हल्का नंबर-16 में स्थित भूमि जिसका कोरबा खसरा नंबर 188/1/क/1 है। उक्त स्थित भूखण्ड 16 एवं 16बी में निर्मित दुकानों के अंतर्गत दुकान क्रमांक 16 जिसका क्षेत्रफल 23'11" x 12'08" वर्गफुट एवं दुकान क्रमांक 17 क्षेत्रफल 24'0" x 13'02" वर्गफुट है। इन दुकानों को विशेष न्यायाधीश (सीजीपीडीआई) कोरबा के दाण्डिक



एम.जे.सी. क्रमांक 21/2022 में 15 नवंबर 2022 को पारित आदेश के अनुसार अत्याधिक आदेश पारित किया गया है। जिसके फलस्वरूप जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा 21 नवंबर 2022 को आदेश पारित कर तहसीलदार कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिपत भूमि का कोरबा कोरबा द्वारा उक्त भूखण्ड की 17 लाख 81 हजार रूपए में नीलामी को कार्यवाही पूर्ण की गई है। नीलामी की राशि को निर्देशानुसार हितग्राहियों को वितरित किया जाना है। तहसीलों से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त कंपनी में जिले के 2394 निवेशकों द्वारा राशि निवेशित की गई है। जिसके निवेशकों

को भुगतान की कार्यवाही किया जाना है। इसी प्रकार सर्वमंगला प्रापटी इंडिया लिमिटेड के निवेशकों को राशि वितरित किया जाना है।

अपर कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को बी. एन. गोल्ड रियल स्टेट एण्ड एलाइड एवं सर्वमंगला प्रापटी इंडिया लिमिटेड के निवेशकों की आवश्यक जानकारी 03 जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा 21 नवंबर 2022 को आदेश पारित कर तहसीलदार कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिपत भूमि का कोरबा कोरबा द्वारा उक्त भूखण्ड की 17 लाख 81 हजार रूपए में नीलामी को कार्यवाही पूर्ण की गई है। नीलामी की राशि को निर्देशानुसार हितग्राहियों को वितरित किया जाना है। तहसीलों से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त कंपनी में जिले के 2394 निवेशकों द्वारा राशि निवेशित की गई है। जिसके निवेशकों

पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम और उनके दामाद के घर एसीबी का छापा

जगदलपुर/कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर और जगदलपुर में एसीबी

की टीम ने गुरुवार सुबह एक साथ छापा मारा है। ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी और उनके बीडीओ दामाद राजेश उपाध्याय के आवास पर चल रही है। ससुर-दामाद दोनों पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। इस मामले में आरोपी अशोक चतुर्वेदी लंबे समय से फरार चल रहे थे। एसीबी की टीम ने उन्हें आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से गिरफ्तार किया था। एसीबी के ईंचार्ज एसपी यूलैनडन यॉर्क ने यह जानकारी दी है।

एसीबी की टीम सुबह करीब 5 बजे जगदलपुर के धरमपुर स्थित राजेश उपाध्याय के घर पहुंची। राजेश उपाध्याय दरभा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं। टीम के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी है। अफसर उनके घर में दस्तावेज खंगाल रहे हैं। राजेश उपाध्याय पंडरीपानी स्कूल में व्याख्याता हैं, लेकिन उन्हें बीडीओ का प्रभार दिया गया है। इसके पहले वे तोकापाल में बीआरसी के पद पर कार्य कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में की जा रही है।

वहीं एक दूसरी टीम दुर्गाकॉलेज में अशोक चतुर्वेदी के आवास पर पहुंची है। वहां भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद अशोक चतुर्वेदी पंचायत विभाग में प्रतिनियुक्ति पर थे। उनके खिलाफ चार मामले दर्ज हैं। इसमें पाठ्य पुस्तक निगम में ग्रीन बोर्ड के टेंडर के नाम पर अपने बेटे को फायदा पहुंचाने, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर पास करवाने और कमेटी को गुमराह करके ठेकेदार को फायदा पहुंचाने का आरोप है। इसके अलावा अनुपातहीन संपत्ति का भी आरोप है।



रेत और गिट्टी का अवैध भंडारण करने पर एसडीएम ने की कार्रवाई

बेमेतरा। पडकोडीह में शासकीय प्राथमिक शाला के पास अवैध रूप से रेत और गिट्टी का भंडारण किया गया था। जिस पर एसडीएम सुरेश सिंह ने कार्रवाई की है। इसके साथ ही एसडीएम ने अवैध रूप से संचालित दवाखानों पर कार्रवाई की है। वहीं झालम मोड़ के पेट्रोल पंप को

व्यवर्तित भूमि का लगान तीन वर्षों से नहीं देने के कारण सील कर दिया है। एसडीएम की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। रेत और गिट्टी समेत वाहन जब - पडकोडीह गांव के व्यापारी गोविंद साहू ने अवैध रूप से रेत और गिट्टी का भंडारण किया था। जिसे एसडीएम सुरेश सिंह ने जब्त किया है। गिट्टी और रेत को मरका गांव के सरपंच के सुपुर्द किया गया है। पडकोडीह में कार्रवाई के दौरान ही हाइवा मोक के पर पहुंची। जिसकी जांच करने पर पाया गया कि वाहन में गिट्टी है लेकिन रॉयल्टी पेपर नहीं है। वाहन चालक से कड़ी पूछताछ के बाद संबंधित वाहन व्यापारी के लिए लाया जाना बताया गया। जिस पर एसडीएम ने वाहन को जब्त करके निगाह थाने के सुपुर्द किया। वहीं गोविंद साहू के खिलाफ दोनों ही मामलों में खनिज विभाग



को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खंडसरा में अवैध दवाखाना सील - एसडीएम सुरेश सिंह ने ग्राम खंडसरा में अवैध रूप से झोलाछाप डॉक्टरों के 2 दवाखाना को सील किया है। एसडीएम सुरेश सिंह ने अवैध रूप से संचालित खंडसरा में संजीवनी होमियोपैथिक क्लीनिक, पायल क्लीनिक के नाम संचालित अवैध दुकानों को सील किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई तरह की दवाइयां खुले में रखी गई थी। झालम मोड़ में वन प्लेनटी फील्ड पेट्रोल पंप का निरीक्षण एसडीएम ने किया। जहां पेट्रोल टंकी संचालनकर्ता ने तीन वर्षों से पेट्रोल पंप स्थित व्यवर्तित भूमि का लगान का भुगतान नहीं किया था। पूछताछ किये जाने पर पेट्रोल पंप संचालक ने जवाब नहीं दिया जिसके बाद पंप को सील कर दिया गया।

घर में घुसकर कृषि विस्तार अधिकारी पर देर रात हमला

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बुधवार देर रात कृषि विस्तार अधिकारी की जान लेने का प्रयास किया गया। घर में घुसकर किसी ने धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला कर दिया। इसमें वह बाल-बाल बच गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कृषि विस्तार अधिकारी को हल्की चोट आई है। मामला भोपालपटनम थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, भोपालपटनम के चेरपल्ली में पदस्थ कृषि विस्तार अधिकारी मुन्ना लाल बघेल क्लब पारा में रहते हैं। बुधवार रात करीब 11 बजे एक युवक पीछे के दरवाजे से घर में घुसा और उनके ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद वहां से भाग निकला। इस हमले में मुन्ना लाल बघेल की कोहनी में चोट आई है। उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भोपालपटनम में इलाज जारी है। इस वारदात के बाद से बस्ती में दहशत है। जगदलपुर निवासी मुन्ना लाल बघेल पांच वर्षों से बीजापुर में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। भोपालपटनम के एसडीओपी ने कहा कि, हमला किस चीज से किया गया है, रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

करंट लगने से मादा भालू और उसके बच्चे की मौत

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में करंट की चपेट में आने से बुधवार देर रात मादा भालू और उसके बच्चे की मौत हो गई। दोनों का शव सुबह खेत में पड़ा मिला तो किसान ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि किसान ने खेत में बोर के लिए तार लगा रखा था, उसी की चपेट में मादा भालू और उसका बच्चा आ गए। वन विभाग ने दोनों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला नरहरपुर परिक्षेत्र का है। नरहरपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी धनलाल साहू ने बताया कि थानाबोडी गांव में प्रेम सिन्हा के खेत में मादा भालू और उसके बच्चे का शव बरामद हुआ है। मादा भालू की उम्र करीब पांच साल और बच्चा चार महीना का होगा। प्रेम सिन्हा ने खेत में सिंचाई के लिए बोर लगाकर विधुत कनेक्शन ले गया था, जिसकी चपेट में भालू आया है। इससे पहले वर्ष 2019 में करंट से तीन भालूओं की मौत हुई थी। जिसमें मादा भालू का नाखून व दांत गायब मिला था। वहीं 2022 के सितम्बर में मकें की फसल बचाने एक किसान ने करंट लगाया था, जहां भालू सहित युवक की भी मौत हो गई थी।

एसडीएम चंद्रकार ने ली पटवारियों की बैठक

महासमुंद। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर महासमुंद द्वारा समय-सोमा बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्रीमती श्रुति चंद्रकार और तहसीलदार श्री प्रेम साहू, नायब तहसीलदार शशि नर्मदा नायक की उपस्थिति में पटवारियों की बैठक ली गई। बैठक में पटवारियों को खसरा का शत प्रतिशत डिजिटल सिग्नेचर, प्रति सप्ताह 20 नक्शा काटने, भुइया के भू अभिलेख में हुई त्रुटियों में सुधार, कोटवारी सेवा भूमि को अहस्तानतरीय दर्ज करने, नामांतरण बटवारा को समय सीमा में दुरुस्त करने आदि के लिए निर्देश दिए गए। पटवारियों को उनके क्षेत्र के ग्रामों में शासकीय भूमि का चिन्हांकन और अतिक्रमण पंजी बनाने, वर्तमान मानसून के मद्देनजर किसी भी प्रकार की जनहानि, पशुहानि और अन्य हानि होने पर तत्काल सूचना देने और ग्रामवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसका पूरा ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में पटवारियों के द्वारा अपने कार्य में आ रही ऑनलाइन तकनीकी परेशानियों की भी चर्चा की।

मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक के लिए बनाया गया

112 स्वास्थ्य शिविर कुटीर

जशपुर। जिला प्रशासन द्वारा दूरस्थ अंचल में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के तहत का बेहतर लाभ देने के लिए जशपुर जिले के 112 हाट बाजारों में स्वास्थ्य शिविर कुटीर बनाया गया है, ताकि मरीजों और डॉक्टरों को धूप, पानी, हवा से सुरक्षित रख सके। चिकित्सकों को मरीजों के इलाज करने में समस्या न हो। अब स्थाई रूप से स्वास्थ्य कुटीर बनने से सुविधाएं और भी बढ़ गई हैं। डॉक्टरों द्वारा इलाज के बाद मरीजों को तत्काल निशुल्क दवाई एवं परामर्श दिया जा रहा है। गांव के ग्रामीणजनों को हाट बाजार के साथ अपने घर के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल रहा है। इससे ग्रामीणजनों को समय के साथ पैसे की बचत हो रही है। अब उन्हें इलाज के लिए दूर-दूर तक जाने की अवाश्यकता नहीं पड़ती। हाट-बाजार में खून जांच, बीपी, शुगर जांच, मलेरिया, टाइफाइड सहित अन्य बीमारियों की भी जांच होता है। इलाज के दौरान गंभीर मरीजों को उच्च अस्पताल में रेफर भी किया जाता है।

गौ पालन से रुक्मणी आर्थिक स्वावलंबन की मिसाल बनी

महासमुंद। महासमुंद जिले के विकासखण्ड बसना के ग्राम पडकोपाली में एक गृहणी श्रीमती रुक्मणी पटेल गौ-पालन कर परिवार को अपना विशेष सहयोग प्रदान कर रही हैं। पडकोपाली के प्रगतिशील सीमांत कृषक परिवार की श्रीमती रुक्मणी पटेल ने गृह कार्य के साथ-साथ अपने बच्चे हुए शेष समय का सदुपयोग कर अपने परिवार का आर्थिक सहयोग करने की ठानी। कृषक परिवार से संबंध होने एवं पूर्व से थोड़ा बहुत पशुपालन की जानकारी होने के कारण विभागीय कर्मचारियों से पशुपालन संबंधी योजनाओं की उनके द्वारा जानकारी ली गई, जिसमें उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य डेयरी उद्योगिता विकास योजना उपयोगी एवं लाभप्रद लगा और उन्होंने इसके लिए वर्ष 2021-22 में विभाग से गौ पालन हेतु स्ववित्तीय आवेदन स्वीकृत करा कर दो गाय ऋय कर अपना डेयरी इकाई प्रारंभ किए। इस कार्य में रुक्मणी पटेल के परिवार जनों ने भी उनका भरपूर सहयोग किया वि बताते हैं कि उनके द्वारा प्रारंभ किए डेयरी इकाई से प्रतिदिन लगभग 25 लीटर दूध उत्पादन होने लगा।

नैनो यूरिया लेने किसानों में बढ़ा रुझान, समितियों के माध्यम से वितरण

कोरबा। मानसून के आगमन के साथ ही जिले के किसान खेती-किसानी के कार्य में व्यस्त हो गए हैं। जिले में धान सहित अन्य फसल किसान खरीफसीजन में लेते हैं। शासन द्वारा किसानों को समय पर खाद एवं वर्मी कम्पोस्ट वितरण की कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा द्वारा भी अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जिले के किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उनके द्वारा खाद-बीज वितरण एवं भण्डारण की जानकारी भी लगातार ली जा रही है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कोरबा के नोडल अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद का भण्डारण है। जिले के किसानों को समय पर खाद का वितरण किया जा रहा है। यूरिया दानेदार के वैकल्पिक रूप में नैनो यूरिया समितियों में भण्डारित है। इसे प्राप्त करने किसानों द्वारा रूचि भी दिखाई जा रही है। उन्होंने बताया कि खरीफवर्ष 2023 अंतर्गत कोरबा जिले में 102200 मीट्रिक टन रासायनिक खाद लक्ष्य के विरुद्ध 84 प्रतिशत खाद का भण्डारण 41 सहकारी समितियों में अब तक किया जा चुका है। साथ ही जिले में यूरिया



दानेदार के वैकल्पिक रूप में नैनो यूरिया (लिक्विड) 5700 लीटर भण्डारित किया गया है। यूरिया दानेदार के वैकल्पिक रूप में उपलब्ध नैनो यूरिया (लिक्विड) के प्रति किसानों का रुझान बढ़ रही है। समितियों में पर्याप्त मात्रा में सभी रासायनिक खाद उपलब्ध है, जिसका उद्योग

कृषकों द्वारा अपनी सुविधा एवं आवश्यकता अनुसार किया जा रहा है, जिन समितियों में यूरिया एवं अन्य खाद की कमी है उन समितियों में भंडारण हेतु आरओ/डीडी जारी करवाये जा रहे हैं। इससे पहले विगत वर्ष इसी समय तक 68 प्रतिशत खाद भण्डारित था, जबकि वर्तमान में लक्ष्य के विरुद्ध 84 प्रतिशत खाद का भण्डारण समितियों में अब तक किया जा चुका है। किसी कृषक को खाद नहीं मिलने जैसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिले के खाद संग्रहण केंद्र (डबल लॉक सेंटर) कटघोरा में 1389 टन, उरगा संग्रहण केंद्र में 2093 टन यूरिया संग्रहण की गई थी। जिसमें कटघोरा में 1135 और उरगा में 2014 टन वितरित किया जा चुका है। इसी तरह डीएपी कटघोरा एवं उरगा संग्रहण केंद्रों में 1360 टन भण्डारित की गई थी। जिसमें से 1145 टन विक्रय किया गया है।

जेल बंदी पहली बार देंगे बोर्ड परीक्षा

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला जेल में विचारधीन कैदी पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। विचारधीन बंदियों में नक्सल, हत्या और दुष्कर्म के आरोपी शामिल हैं। जेल से परीक्षा देने वाले बंदियों की फीस जिला प्रशासन की ओर से खनिज न्यास निधि से जमा कराई जाएगी। इसके लिए स्वीकृति कलेक्टर ने दे दी है। साथ ही ओपन समन्वय केंद्र कांकेर की ओर से इन्हें निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक 12 बंदियों ने फार्म भरा है। नक्सल मामलों में बंदी एक कैदी ने बताया कि, उसने 10वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन फेल हो गया था। वह 2020 से जेल में बंद है। इस दौरान उसे पता चला कि जेल में रहते परीक्षा दे सकता है, इस पर उसने भी फार्म भरा है। बंदी ने बताया कि उसके ऊपर नक्सल पड़ना सप्लाई का आरोप है। कहा कि, वह आगे सजा चाहता है। जेल में यह सुविधा मिल रही है तो इसका लाभ ले रहा है। नक्सल मामलों में बंद दो बंदियों ने परीक्षा का फार्म भरा है। ये बंदी राज्य



ओपन बोर्ड की 10 वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं। जिला जेल के जेलर एसएल नायक ने बताया कि कलेक्टर के मार्गदर्शन में बंदियों को बोर्ड परीक्षा देने प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। अनमति मिलने के बाद प्रति सोमवार बंदियों की परेड के दौरान पूछा गया तो और फार्म भरने की बात बताई गई। इस पर 25 से 30 बंदियों ने परीक्षा देने में रूचि दिखाई। हालांकि अभी तक 12 बंदियों ने फार्म भरा है। इसमें नौ ने 10वीं और तीन ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए फार्म भरे हैं। इसकी परीक्षा दो सेमेस्टर सितंबर 2023 और अप्रैल 2024 में होगी। परीक्षा सेंटर कांकेर जेल ही होगा।

केंद्र ने मानसून सत्र से पहले 19 को बुलाई सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा, जो अगले महीने 11 अगस्त तक चलेगा। संसद के इस सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी), दिल्ली सरकार से जुड़े अध्यादेश, महंगाई मण्डल विधेयक जैसे मुद्दों को लेकर हंगामा मचाने के आसार हैं। सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है क्योंकि विपक्षी दल अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। केंद्र ने बुधवार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिससे प्रभावी रूप से भारत के पहले गोपनीयता कानून का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रस्तावित कानून संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है। संसद का मानसून सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता की जोरदार वकालत की है और इस मुद्दे पर परामर्श बढ़ाने के कदम उठाए हैं। संसद का मानसून सत्र 23 दिनों तक चलेगा और इसमें 17 बैठकें होंगी।

सिसोदिया ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है। जिसमें उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया। सिसोदिया इससे पहले सत्र कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर चुके हैं। लेकिन अभी तक राहत नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ राजउ एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को मनीष सिसोदिया की पेशी हुई। जहां कोर्ट ने मनीष की हिरासत को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया को बड़ी राहत दी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया को पेश करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर की थी। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि उन्हें प्रभावी सुनवाई के लिए शारीरिक रूप से पेश होने का अधिकार है।

लालू यादव ने नरेंद्र मोदी और अजित पवार पर साधा निशाना

पटना। महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। वहीं, महाराष्ट्र के बाद बिहार को लेकर भी राजनीतिक चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर से लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजित पवार पर निशाना साधा है। दिल्ली रवाना होने से पहले लालू यादव ने पटना में कहा कि 2024 में देश से नरेंद्र मोदी को हटाना है। इसके साथ ही उन्होंने अजित पवार के बयान पर कहा कि राजनीति में बूढ़ा आदमी कभी रिटायर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट लोगों के संचालक हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री जिन्हें भ्रष्ट कहते थे, उन्हें को महाराष्ट्र में मंत्री बना दिया है। लालू यादव ने शरद पवार का समर्थन करते हुए अजित पवार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि भतीजे अजित के कहने से शरद पवार रिटायर नहीं हो जाएंगे। बूढ़ा आदमी राजनीति में कभी रिटायर नहीं होता है। लालू ने दावा किया कि शरद पवार मजबूत नेता हैं। भतीजे अजित पवार का कोई असर नहीं है।

नियुक्ति के लिए एलजी की मंजूरी आदेश पर भड़के केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले सभी विभागों में उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना किसी भी सलाहकार, फेलो और स्पेशलिस्ट की नियुक्ति पर रोक लगने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक ट्वीट के जरिए उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के एक नए आदेश से दिल्ली सरकार की सेवाएं और कार्यप्रणाली पूरी तरह से बाधित हो जाएगी, जिसमें उनकी मंजूरी के बिना सैकड़ों सलाहकारों और सहयोगियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले को लेकर केजरीवाल ने कहा, एलजी पूरी तरह से सरकार और उनकी सेवाओं का गला घोट देंगे। मुझे नहीं पता कि यह सब करने के एलजी को क्या मिलेगा? मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे तुरंत रद्द कर देगा। गौरतलब है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अलग-अलग विभागों से जुड़े बोर्ड, आयोग और कमेटियों में 437 लोगों को फेलो, एसीएसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, सीनियर रिसर्च अधिकारी आदि पदों पर नियुक्ति की गई थी।

महाराष्ट्र में लोकतंत्र नहीं, यह तमाशा है : कपिल सिब्बल

नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम को तमाशा बताते हुए गुरुवार को कहा कि ऐसा लगता है कि कानून ऐसा करने की इजाजत दे रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक घटनाक्रम सत्ता की रोटियां सेंकने को लेकर है...लोगों की भलाई के लिए नहीं। राकांपा के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में गत रविवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं पार्टी के आठ अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी। सिब्बल ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र की राजनीति...यह लोकतंत्र नहीं है। यह तमाशा है और ऐसा लगता है कि कानून ऐसा करने की इजाजत दे रहा है। यह सत्ता की रोटियां सेंकने के बारे में है...लोगों के बारे में नहीं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को कहा था कि वह मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं और उन्होंने शरद पवार पर तंज कसते हुए सवाल किया कि वह सक्रिय राजनीति से कब सेवानिवृत्त होंगे।

राजस्थान में मिलकर चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस : वेणुगोपाल

सितंबर के पहले हफ्ते में प्रत्याशियों का होगा एलान, जो जीत सकेगा उसी को मिलेगा टिकट

जयपुर। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में एआईसीसी मुख्यालय में हुई बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। केसी वेणुगोपाल ने साफ किया कि सितंबर महीने के पहले सप्ताह में इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए टिकट फाइनल करके टिकट वितरण कर दिया जाएगा। इस बार जल्दी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट घोषित कर दिए जाएंगे।

कांग्रेस संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने स्पष्ट किया कि सात जुलाई से ही चुनाव कैम्पेनिंग राजस्थान में शुरू कर दी जाएगी। आगामी दिनों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत कांग्रेस के तमाम नेता राजस्थान में चुनाव कैम्पेन करने आएंगे। बैठक में सचिन पायलट और अशोक गहलोत समेत तमाम नेता बैठक में जुड़े। राजस्थान के 29 लीडर दिल्ली पहुंचे। सीएम अशोक गहलोत जयपुर से जूम मीटिंग से ऑनलाइन लाइव जुड़े। इसके अलावा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। 33 लीडर्स मीटिंग में शामिल हुए।

वेणुगोपाल ने कहा, राजस्थान के सभी नेताओं ने एकजुटता से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वेणुगोपाल और प्रभारी रंधावा ने स्पष्ट किया अब कोई डिफरेंस पार्टी नेताओं में नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले डिफरेंसेज थे। लेकिन अब सभी नेता एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। बाहर पब्लिक में कोई नेगेटिविटी के साथ बात नहीं करेंगे। कोई समस्या है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडरशिप को बताई जा सकती है।

राजस्थान कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई भी कांग्रेस नेता एक शब्द नहीं बोलेंगा

संगठन महासचिव ने बैठक का डिसीजन बताया कि कांग्रेस पार्टी और राजस्थान कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई भी कांग्रेस नेता एक शब्द भी नहीं बोलेंगा। पूरी यूनिटी और पॉजिटिविटी के साथ चुनाव कैम्पेनिंग में सभी नेता उतरेंगे। यदि कोई नेता पार्टी या सरकार के खिलाफ पार्टी



प्लेटफॉर्म के बाहर पब्लिक डोमेन में बोलता है, तो उसके खिलाफ रिस्ट्रिकली अनुशासन की कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया जाएगा।

सीएम फेस पर बोले वेणुगोपाल कांग्रेस की हिस्ट्री आप जानते हो...

वेणुगोपाल ने स्पष्ट किया कि सीएम अशोक गहलोत को सरकार प्रदेश में अच्छा काम कर रही है। सरकार की नीतियों और योजनाओं का फायदा चुनाव में मिलेगा। जब मीडिया ने सवाल किया कि सीएम फेस कौन रहेगा? तो वेणुगोपाल ने इशारा देते हुए कहा, कांग्रेस की हिस्ट्री आप जानते हैं। यहां पहले से सीएम फेस घोषित नहीं किया जाता है। लेकिन प्रदेश में गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही है, उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। यह बात वेणुगोपाल ने कहकर स्पष्ट इशारा दे दिया कि गहलोत ही चुनावी चेहरा रहेंगे।

जिताऊ कैडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा सर्वे किए जा रहे

केसी वेणुगोपाल ने कहा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मीटिंग कलेंडर कर ली है। कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में भी इस बार जल्दी टिकट वितरित किए जाएंगे। वेणुगोपाल ने कहा, विनेबिलिटी के आधार पर ही टिकट का वितरण किया जाएगा। इसमें किसी तरह का समझौता नहीं होगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी कई तरह के

सर्वे करवा रही है। केवल जिताऊ कैडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम आसानी से बीजेपी को राजस्थान समेत पांच राज्यों में चुनाव हराएंगे।

सचिन पायलट की मांगों पर राजस्थान कांग्रेस सरकार एक्शन ले रही

केसी वेणुगोपाल और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह भी स्पष्ट किया कि सचिन पायलट की मांगों पर राजस्थान कांग्रेस सरकार एक्शन ले रही है। आरपीएससी में निष्पक्षता के आधार पर और योग्य लोगों को ही पदों पर लिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा में पेपर लीक मामले पर राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार उग्र कदम की सजा का सख्त बिल लेकर आ रही है। वेणुगोपाल और रंधावा ने कहा, सचिन पायलट भी बैकट में मौजूद रहे। जिन्होंने पॉजिटिव वे में अपनी पूरी बात रखी और एकजुटता से चुनाव लड़ने की बात कही। साथ ही पायलट ने कहा राजस्थान में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी।

मानहानि मामले में अशोक गहलोत को दिल्ली कोर्ट का समन

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 900 करोड़ रुपये के क्रेडिट सोसायटी घोटाले के संबंध में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तलब किया है। उन्हें 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। यह समन एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जस्टिस हरजीत सिंह जसपाल ने जारी किया था। राजउ एवेन्यू कोर्ट ने पहले इस पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था कि आपराधिक मानहानि मामले में मुख्यमंत्री को समन जारी किया जाए या नहीं। बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर करने के लिए राजउ एवेन्यू अदालत का रुख किया था। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि राजस्थान के सीएम ने संजीवनी क्रेडिट सोसायटी घोटाले में पूर्व की कथित सल्लसता के संबंध में उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए।

शरद पवार का अजित को जवाब

अभी भी मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ : पवार

नईदिल्ली। महाराष्ट्र में एनसीपी के भीतर वर्चस्व को लड़ाई जारी है। एक ओर जहां अजित पवार गुट दावा कर रहा है कि एनसीपी पर हमारा कब्जा है। तो वहीं शरद पवार गुट भी साफ तौर पर कह रहा है कि एनसीपी तो हमारे पास है। इन सबके बीच दिल्ली में आज शरद पवार गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद शरद पवार ने साफ तौर पर कहा कि अभी भी मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं चाहें मैं 82 का हूँ या फिर 92 का हो जाऊँ, अभी भी मैं प्रभावी हूँ। इसके जरिए शरद पवार ने अजित पवार को जवाब दिया जिसमें उन्होंने वरिष्ठ नेता को रिटायर लेने की सलाह दी थी।

शरद पवार ने कहा उम्र 82 की हो या 92 की, मायने नहीं रखती है। अजित पवार के दावों पर उन्होंने कहा कि उनके दावा में कोई सच्चाई नहीं है। मैं अभी भी एनसीपी का अध्यक्ष हूँ और कौन क्या कह रहा है इसके बारे में मुझे पता नहीं है। मेरे पास किसी और के कहने की कोई अहमियत नहीं है। कोई सीएम बनना चाहता है तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि अब हमें जो भी कहना होगा हम भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कहेंगे। उन्होंने कहा कि आज की बैठक से हमारा मनोबल बढ़ाने में मदद मिली...मैं राकांपा का अध्यक्ष हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि जिन लोगों को निष्कासित किया, उनको छोड़कर बाकि अन्य लोग इतने कम समय में बैठक के लिए आए। हमारे सभी साथियों की मानसिकता पार्टी को मजबूती से आगे ले जाने की रही।

दिल्ली की बैठक में 8 प्रस्ताव पास, सभी ने शरद पवार पर पूरा भरोसा जताया

एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर पीसी चाको ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने आज 8 प्रस्ताव पारित किये। समिति ने पार्टी अध्यक्ष शरद पवार पर पूरा भरोसा जताया है।



इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और एनडीए से हाथ मिलाने वाले 9 विधायकों को बाहर करने के शरद पवार के फैसले को मंजूरी दे दी है।

पीसी चाको ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय कमेटी तालकटोरा स्टेडियम में मिली थी जिसमें शरद पवार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित किया है। पार्टी की 27 इकाइयां हैं। इन सभी 27 राज्य इकाइयों ने एनसीपी के साथ रहने की बात कही है। किसी भी एक इकाई ने यह नहीं कहा कि वह शरद पवार के साथ नहीं है। वहीं, अजित पवार गुट ने कहा कि दिल्ली में शरद पवार द्वारा बुलाई गई राकांपा कार्यसमिति की बैठक की कोई कानूनी वैधता नहीं है।

अजित 30 जून को राकांपा अध्यक्ष चुने गए

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने निर्वाचन आयोग को सूचित किया है कि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के मुताबिक, निर्वाचन आयोग को एक हलफनामे के माध्यम से सूचित किया गया है कि उन्हें 30 जून, 2023 को राकांपा के सदस्यों, विधायी और संगठनात्मक, दोनों इकाइयों के 'भारी बहुमत' द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव के माध्यम से राकांपा प्रमुख चुना गया। बयान में कहा गया है कि प्रफुल्ल पटेल राकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे।

खेल प्रमुख समाचार

विश्व कप से पहले बांग्लादेश के कप्तान ने अचानक लिया संन्यास

ढाका। बांग्लादेश के वनडे कप्तान तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। वह पहले ही टी20 प्रारूप से संन्यास ले चुके थे और आखिरी बार उन्होंने अप्रैल में टेस्ट खेला था। फिलहाल बांग्लादेश अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेल रही है। टीम शुक्रआती मैच हार गई जबकि तमीम पहले वनडे में कुछ खास कमाल नहीं कर सके हैं। ऐसी खबरें भी आई थीं कि वह ओपनर के लिए फिट नहीं हैं लेकिन फिर भी उन्होंने खेलने का फैसला किया था। तमीम इकबाल ने दोपहर 12 बजे (स्थानीय समयानुसार) अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और संन्यास की घोषणा की।

दावा किया जा रहा कि वह बेहद भावुक थे और घोषणा करते समय रो भी पड़े। तमीम का फैसला बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बड़ा झटका है, जबकि भारत में विश्व कप शुरू होने में केवल तीन महीने बचे हैं। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए अंत है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। मैं इसी क्षण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूँ। मैं अपनी टीम के सभी साथियों, कोचों, बीसीबी अधिकारियों, अपने परिवार के सदस्यों और उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरी लंबी यात्रा में मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझ पर विश्वास बनाए रखा। मैं प्रशंसकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके प्यार और मुझ पर विश्वास ने मुझे बांग्लादेश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित किया। मैं अपने जीवन के अगले अध्याय के लिए आपकी प्रार्थनाएँ माँगना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखें। टाइमिंग पहले ही मुख्य कार्यक्रम के लिए कालीफाई कर चुके हैं और अब इस प्रारूप में खेलने का कोई कप्तान नहीं बचा है। शाकिब अल हसन इस समय टी20ई कप्तान हैं जबकि लिटन दास टेस्ट में बांग्लादेश का नेतृत्व करते हैं।

सेंसेक्स 340 अंक बढ़ा निपटी 19,500 के करीब

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखी गई। आज के कारोबार में बाजार की शुरुआत धीमी रही और बाद में मुनाफावर्षूली का झिलझिला चलने से उनका लाभ सिमट गया। इसके बावजूद शेयर बाजार अपने ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गए। आज के कारोबार में संसेक्स 340 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निपटी में भी 99 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के अंत में निपटी 19,497.30 पर बंद हुआ। व्यापक बाजारों ने अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रखा। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में 0.4 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। पिछले कुछ सत्रों से शेयर बाजार लगातार नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक संसेक्स 339.60 अंक यानी 0.52 फीसदी मजबूत होकर 65,785.64 अंक पर बंद हुआ।

पीएफसी ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी को धन उपलब्ध कराया

नईदिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की पवार फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को 9,187 करोड़ रुपये का वित्त प्रदान किया है। पीएफसी ने वृहत्स्पतिवार को बयान में यह जानकारी दी। यह पहली परियोजना है जबकि पीएफसी ने रिफाइनरी और पेट्रोरेसायन क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। बयान में कहा गया है कि पीएफसी न केवल बिजली क्षेत्र, बल्कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र के जरिये भी राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे रही है। महारथ कंपनी और बिजली क्षेत्र में देश की प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पीएफसी ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लि. को राजस्थान के बाइसेमर में स्थित 90 लाख टन सालाना क्षमता के रिफाइनरी एवं पेट्रोरेसायन परिसर के लिए 9,187 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं।

जियो विस्तार के लिए नोकिया से खरीदेगी 5जी उपकरण

नईदिल्ली। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो इस साल के अंत तक पूरे भारत में 5जी मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में कंपनी एक और कदम आगे बढ़ाने वाली है। कथित तौर पर जियो नेटवर्क विस्तार के लिए नोकिया के 5जी उपकरण में 14,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस जियो इन्फोकॉम 5जी नेटवर्क उपकरण खरीदने के लिए फिनलैंड स्थित एक प्रमुख टेलीकॉम कंपनी नोकिया के साथ लगभग 1.7 अरब डॉलर (14,000 करोड़ रुपये) के एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने की कगार पर है। कॉन्ट्रैक्ट पर गुरुवार, 6 जुलाई को हेलसिंकी के पास नोकिया के मुख्यालय में हस्ताक्षर होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी और इस डील के लिए फंडिंग करने वाले बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

जून में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 10 फीसदी बढ़ी : फाडा

नईदिल्ली। घरेलू बाजार में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री जून में 10 फीसदी बढ़ी है। इनमें यात्री वाहन और दोपहिया शामिल हैं। वाहन डीलर संघों के महासंघ (फाडा) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पिछले महीने वाहनों कुल खुदरा बिक्री एक साल पहले की समान अवधि के 17,01,105 इकाई के आंकड़े से बढ़कर 18,63,868 इकाई हो गई। जून में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री पांच प्रतिशत बढ़कर 2,95,299 इकाई पर पहुंच गई। जून, 2022 में घरेलू बाजार में 2,81,811 यात्री वाहन बेचे गए थे। इसी तरह, पिछले महीने दोपहिया वाहनों की बिक्री सात प्रतिशत बढ़कर 13,10,186 इकाई पर पहुंच गई। एक साल पहले समान महीने में 12,27,149 दोपहिया बिके थे। तिपहिया वाहनों की बिक्री पिछले साल जून के 49,299 इकाई के आंकड़े से 75 प्रतिशत बढ़कर 86,511 इकाई हो गई।

वेस्टइंडीज के बिना विश्व कप क्रिकेट, सभी के लिए सबक

राज कुमार सिंह

क्रिकेट के वास्तविक प्रशंसकों के लिए यह सद्मे से कम नहीं कि पहले दो विश्व कप जीतने वाली वेस्टइंडीज की टीम 48 साल में पहली बार विश्व कप के लिए क्वालीफाई हो गई। लेकिन वेस्टइंडीज का 60-70 और 80 के दशक में जैसा दबदबा रहा, उसकी मिसाल नहीं मिलती। गार्नर, होल्डिंग, रॉबर्ट्स की आग उगलती गेंदों के आगे बल्लेबाज कांपते थे, तो लॉयड, रिचर्ड्स और सोबर्स के आगे गेंदबाज लड़खड़ाते थे। हेंस और ग्रीनिंग से ज्यादा आक्रामक सलामी जोड़ी शायद ही हुई हो। जानना दिलचस्प होगा कि बतौर स्पिनर अपना टेस्ट कैरियर शुरू करने वाले सोबर्स का 365 रन का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड 36 साल बाद टूट पाया था। ऐसी गौरवशाली विरासत वाली वेस्टइंडीज क्रिकेट आज अगर वन डे विश्व कप के लिए क्वालीफाई भी न कर पाए की

गुणाना, जमैका, त्रिनिदाद, लेवर्ड आइलैंड, टोबेगो और विंडवर्ड जैसे छोटे-छोटे द्वीप - देशों के खिलाड़ियों से चुनी जाती है। क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ। ऑस्ट्रेलिया उसका परंपरागत प्रतिद्वंद्वी होता, लेकिन वेस्टइंडीज का 60-70 और 80 के दशक में जैसा दबदबा रहा, उसकी मिसाल नहीं मिलती। गार्नर, होल्डिंग, रॉबर्ट्स की आग उगलती गेंदों के आगे बल्लेबाज कांपते थे, तो लॉयड, रिचर्ड्स और सोबर्स के आगे गेंदबाज लड़खड़ाते थे। हेंस और ग्रीनिंग से ज्यादा आक्रामक सलामी जोड़ी शायद ही हुई हो। जानना दिलचस्प होगा कि बतौर स्पिनर अपना टेस्ट कैरियर शुरू करने वाले सोबर्स का 365 रन का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड 36 साल बाद टूट पाया था। ऐसी गौरवशाली विरासत वाली वेस्टइंडीज क्रिकेट आज अगर वन डे विश्व कप के लिए क्वालीफाई भी न कर पाए की



शर्मिंदगी से रूबरू है, तो इसके लिए उसके क्रिकेटर ही जिम्मेदार हैं, जिनके लिए पैसा देश से बढ़कर हो गया है। उसके अपने खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने के बजाय दुनिया भर में टी-20 लीग खेलने में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उससे पैसा ज्यादा मिलता है। कुछेक अपवादों को छोड़ दें, तो उस स्तर के खिलाड़ी अब वेस्टइंडीज में ढूँढे नहीं मिलते। कभी खिलाड़ी नेशनल कैप पहन कर मैदान में उतरना गौरव समझते थे, अब एकसूत्रीय लक्ष्य लीग क्रिकेट खेलकर ज्यादा पैसा कमाना बन गया है। वेस्टइंडीज

क्रिकेट के महानायकों में शुमार माइकल होल्डिंग की पीढ़ा है कि टी-20 फ्रेंचाइजी लीग तथा जैसे के पीछे दौड़ में देश और असली क्रिकेट, दोनों पीछे छूट गए हैं। बेशक पैसा भी जरूरी है, क्योंकि खिलाड़ियों का खेल जीवन लंबा नहीं होता, पर कितना? अगर आप दौलत और शोहरत के शिखर पर खड़े भारतीय क्रिकेटरों से तुलना करेंगे, तो वाकई क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) अपने खिलाड़ियों को उताने नहीं दे पाता। अनुमानतः भारत में एक टेस्ट खेलने के लिए 15 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि वेस्टइंडीज में लगभग पौने पांच लाख। इसी तरह वन डे और टी-20 में भारत में क्रमशः आठ और चार लाख मिलते हैं, जबकि वेस्टइंडीज में 1.88 और 1.42 लाख रुपये, पर सवाल है कि हर क्रिकेटर बोर्ड दुनिया के सबसे अमीर भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड की बराबरी कैसे कर सकता है?

वैसे सीडब्ल्यूआई अपने खिलाड़ियों से केंद्रीय अनुबंध भी करता है, जिसके तहत कम से कम दो प्रारूप खेलने पर सालाना लगभग दो करोड़ रुपये कमाए जा सकते हैं, जबकि तीनों प्रारूप खेलकर लगभग ढाई करोड़। इसमें मैच फीस भी शामिल है, पर दूसरी और भारतीय आईपीएल में ही वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन को लखनऊ सुपर जाइंट्स ने 16 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा। कोलकाता नाइट राइडर्स से रसेल को भी 16 करोड़ मिले, तो हेमचंद्र को राजस्थान रॉयल्स से साढ़े आठ करोड़। अब तो ऐसा बाजार क्रिकेट दुनिया के कई देशों में होने लगा है। इसका मुकामला सीडब्ल्यूआई के वश से बाहर है। फिर भी, होल्डिंग की मानें, तो 95 प्रतिशत कैरेबियाई नागरिक जितना कमताते हैं, उससे तो ज्यादा ही वहां के क्रिकेटरों को मिलता है। बेशक यह संकट फिलहाल वेस्टइंडीज का है, लेकिन सबक सभी के लिए है।

आतंकवाद पर मोदी का चीन-पाकिस्तान पर प्रहार

ललित मोहन बंसल

दुनिया में आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। चीन के शब्दकोश में सीमा पर आतंकवाद, एक दूसरे की सीमाओं के प्रति सम्मान, अखंडता और सार्वभौमिकता जैसे शब्दों के मायने बदल गए हैं। दूसरी ओर, रूस ने एक कदम आगे बढ़कर अपने अजेडे में दो देशों के बीच गतिरोध को खत्म करने में आपसी बातचीत और कूटनीति को ठेगा दिखा दिया है। इस यूरेशियाई क्षेत्र में तीसरी महाशक्ति भारत है। भू-राजनैतिक कारणों से भारत ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी कायम की है। शायद इसी का असर है कि शिंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की मंगलवार को हुई शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सुनाते हुए कड़े शब्दों में कहा, 'आतंकवाद किसी रूप में हो, उसकी एससीओ मंच से एक स्वर में निंदा होनी चाहिए। इसमें दोहरे मापदंड का कोई स्थान नहीं है।' यह समझा जाना जरूरी है कि रूस और चीन, दोनों ही एससीओ की मूल भावना से भटक रहे हैं। चीन की गिरफ्त में छोटे-छोटे देश आ रहे हैं। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) परियोजना में अरबों डॉलर लगाए हैं। वह दुनिया में नंबर वन बनने के लिए कमजोर देशों को ऋण मुहैया कराने में जुटा है। आज श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार सहित कई अफ्रीकी देश इस कथित सस्ते ऋण के चक्कर में कंगाली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई के लीज दस्तावेज की इबारत ऐसी लिखी गई है कि दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देश इसकी जकड़ में आ गए हैं। भारत की मेजबानी में एससीओ की 23वीं वार्षिक बैठक में ईरान और बेलारूस जुड़े। आज छोटे-छोटे देशों की भारत से अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। मेजबान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आतंकवाद पर किसी भी तरह की रियायत देना गलत बताया। इसके साथ उन्होंने इशारों में चीन और पाकिस्तान के रवैये को तीखी आलोचना की, लेकिन 'वसुधैव कुटुंबकम्' का जिक्र करते हुए भारत का उदार नजरिया पेश करने से भी नहीं चूके। मोदी ने कहा, 'भारत दुनिया भर के देशों को एक परिवार मानता है।' उनका कहना था कि भारत ने बैठकों में इस एससीओ को एक 'विस्तारित पड़ोस' नहीं बल्कि 'विस्तारित परिवार' मान कर काम किया है। मगर मौजूदा हालात में एससीओ से जो अपेक्षाएं थीं, उन्हें देखते हुए इसकी सीमाएं भी स्पष्ट हैं। क्षेत्र की तीन बड़ी शक्तियों के बावजूद शिखर बैठक में एकजुटता के बारे में कोई स्पष्ट रूपरेखा सामने नहीं लाई गई। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बावजूद भारत-अमेरिका के बीच ऐतिहासिक संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के बारे में टिप्पणी करने से परहेज किया गया। भारत एक तटस्थ देश है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वह अमेरिका के ज्यादा करीब आया है। इस मंच से यूक्रेन युद्ध के बारे में सदस्य देशों के मन जो भी विचार रहे हों, टिप्पणी नहीं की गई। इन सबसे एससीओ की कमजोरी झलकती है। लेकिन इसके पॉजिटिव पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वर्चुअल बैठक में मेजबान नरेंद्र मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको और अगले मेजबान कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कस्यम-जोमारट टोकैव अनेक राष्ट्रप्रमुख थे। इन सभी ने इस ओर ध्यान दिलाया कि यह सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है, जब वैश्विक स्तर पर अफरा-तफरी मची है, आतंकवाद और अतिवाद का प्रकोप छाया हुआ है। ऐसे में विश्व में शांति और स्थायित्व के लिए एससीओ बड़ी भूमिका निभा सकता है। पुतिन ने बैठक में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी से सलाह-मशविरा किया था। मोदी ने उन्हें यूक्रेन युद्ध के निदान के लिए परस्पर बातचीत और राजनयिक वार्ता का सुझाव दिया था। दिलचस्प है कि बैठक में पुतिन ने इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया और चीनी समर्थन की विशेष सराहना की।

छत्तीसगढ़ में मोदी-शाह संभालेंगे कमान

समीर चौगांवकर

भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपना फोकस अब इसी साल अक्टूबर नवंबर में होने जा रहे पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और मिजोरम पर फोकस कर दिया है। लगातार इन राज्यों में केन्द्रीय नेताओं के दौरों के साथ संगठन की बैठकें आयोजित होने लगी हैं। भाजपा हाईकमान को इन पांच राज्यों में एक समय भाजपा की सबसे मजबूत कड़ी रही छत्तीसगढ़ इस समय सबसे कमजोर कड़ी नजर आ रहा है। इस कारण मोदी और शाह ने छत्तीसगढ़ पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। भाजपा हाईकमान के पास छत्तीसगढ़ से जो खबर आ रही है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकप्रियता में बढ़त बनाए हुए हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस की लगातार दूसरी बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनने की पूरी संभावना है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस को मिल रही बढ़त और छत्तीसगढ़ भाजपा में नेताओं के बीच जारी मतभेद को लगाम लगाने के लिए गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद संगठन की बैठक लेने 5 जुलाई की शाम को छत्तीसगढ़ पहुंचे।

जून महीने में भी अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे, तब शाह ने 22 जून को दुर्ग में जनसभा को संबोधित किया था। एक जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बिलासपुर में दौरा हो चुका है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि शाह के निर्देश पर 175 कार्यकर्ताओं की विशेष टीम पिछले महीने से छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा कर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति का जमीनी रिपोर्ट तैयार कर अमित शाह को सौंपा है। अपने ताजा दौरों के दौरान अमित शाह इसी रिपोर्ट को वरिष्ठ नेताओं से साझा करेंगे और जरूरी दिशा निर्देश देंगे। इसी के आधार पर प्रदेश के नेताओं को रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपेंगे। एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के बाद उससे 90 विधानसभा सीटें मिलीं। इसमें से 39 सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों में से 29 सीटें अनुसूचित जनजाति और 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 51 सीटें सामान्य वर्ग से हैं लेकिन इन सामान्य सीटों में भी करीब एक दर्जन सीटों पर अनुसूचित जाति वर्ग का खास प्रभाव है। प्रदेश के मैदानी इलाकों की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की भी भारी संख्या है। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 47 प्रतिशत है। मैदानी इलाकों से करीब एक चौथाई विधायक इसी वर्ग से विधानसभा में चुनकर आते हैं। 2003 के विधानसभा चुनाव से



पिछड़े वर्ग की सीटों पर भाजपा का दबदबा था लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में एससी के लिए आरक्षित 10 सीटों में से 6 सीटें जीत लीं और एएसटी के लिए आरक्षित 29 सीटों में से 25 सीटें जीत ली थीं।

एससी, एसटी और आदिवासी वोटर्स के सहारे लगातार 15 साल छत्तीसगढ़ में राज करने वाली भाजपा एक बार फिर पिछड़ों के वोट के सहारे छत्तीसगढ़ में सत्ता पाना चाहती है। इसके लिए अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए भाजपा ने प्रदेश में कई बदलाव किए थे। तीन बार के विधायक नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष और बिलासपुर से सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर को छत्तीसगढ़ के संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। ओम माथुर लगातार छत्तीसगढ़ में कैम्प कर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में भाजपा का कमजोर पक्ष यह भी रहा है कि भाजपा भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कोई मूवमेंट खड़ा नहीं कर सकी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूपेश बघेल के सामने चेहरे के अभाव की है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को प्रदेश की राजनीति से लगभग बाहर कर दिया गया है। फिलहाल भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती दे सके। इसलिए चेहरे की बजाय संगठन के बल पर

भाजपा भूपेश बघेल को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में तय है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी।

वहीं भूपेश बघेल प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने लगभग हर वर्ग को साधने की कोशिश किया है। कर्ज माफी से लेकर बेरोजगारी भत्ता तक कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिला है। जहां तक प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की राजनीति का बड़ा समीकरण है तो वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी वर्ग से आते हैं। इसलिए कांग्रेस पहले ही भूपेश बघेल के जरिए बैकवर्ड क्लास का कार्ड खेल रही है। वहीं भाजपा के आदिवासी नेता नंद कुमार साय के पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले जाने से भाजपा को तगड़ा झटका भी लगा है। पार्टी को झटकों से उबारने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने 7 जुलाई को रायपुर आए। गौरतलब है कि पूरे भारत का भ्रमण करने वाले मोदी चार साल बाद छत्तीसगढ़ आए। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी 8 फरवरी 2019 को रायपुर आए थे। 7 जुलाई को अपने रायपुर दौरों के दौरान मोदी रायपुर को 7 हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। मोदी 268 करोड़ रुपये से बनी रेलवे लाइन का उद्घाटन करने के साथ इंडियन ऑयल के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही मोदी भारतमाला योजना और आईआईआईटी का भी भूमिपूजन करेंगे।

अगर भाजपा प्रदेश में चुनावी रूप से सक्रिय हो रही है तो कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बना दिया है। छत्तीसगढ़ की पहली बार उपमुख्यमंत्री का पद मिला है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 15 साल बाद सत्ता में हुई वापसी में घोषणा समिति के अध्यक्ष रहे तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव की भूमिका महत्वपूर्ण थी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की दौड़ में भूपेश बघेल के अलावा टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत भी थे। लेकिन बाजी भूपेश बघेल के हाथ लगी। कहा गया था कि ढाई-ढाई साल का फार्मूला छत्तीसगढ़ में लागू होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भूपेश बघेल पूरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बन गए। अब ऐसे में चुनाव के पांच महीने पहले टीएस सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बनाकर असंतोष को साधने की कोशिश की गई है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से अभी कांग्रेस के पास 71 और भाजपा के पास 14 सीटें हैं। लोकल बॉडीज इलेक्शन में कांग्रेस का दबदबा रहा है।

प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों पर कांग्रेस का कब्जा है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 43.2 प्रतिशत वोट मिले थे, वहीं भाजपा को 32.9 प्रतिशत वोट मिले थे। इससे पहले 2013 में कांग्रेस को 40.3 प्रतिशत वोट मिले थे वहीं भाजपा को 2013 में 41 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे। बीएसपी को यहां पर साल 2013 में 4.3 प्रतिशत वोट मिले थे। 2018 के चुनाव में बीएसपी ने अजीत जोगी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इन चुनावों में पार्टी को 10.7 प्रतिशत वोट हासिल हुए। अब अजीत जोगी नहीं हैं और बसपा का भी आधार सिकुड़ गया है। ऐसे में पिछले चुनाव में जोगी और बसपा को संयुक्त रूप से मिले 10 प्रतिशत वोट पर नजर कांग्रेस और भाजपा दोनों की है।

भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस और उसके बीच के 11 प्रतिशत वोट के फायदे को पटना है। कांग्रेस जहां भूपेश बघेल की लोकप्रियता पर सवार होकर चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के संगठन कौशल पर निर्भर है। कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ का पूरा चुनाव अभियान जहां प्रदेश नेतृत्व के हवाले कर दिया है वहीं भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने पूरा चुनाव मोदी और शाह के भरपूर छोड़ दिया है। इस कारण मोदी और शाह को छत्तीसगढ़ में ताकत और तैयारियां का जायजा लेने आना पड़ रहा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की कमान शाह ने संभाल ली है। इसका संगठन में कितना असर होगा, यह आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

त्रिपुरोपनिषद् (भाग-4)

गतांक से आगे...
इसी प्रकार हीन वर्ण वाले विधिवत् तैयार किये गये अपने भोज्य पदार्थ (मांस-मदिरा आदि) को (आत्मीय भोग बुद्धि का परित्याग करके) सर्वप्रथम महादेवी को समर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण कर पुण्य कर्मों के द्वारा (श्रेष्ठ कर्मों की) सिद्धि प्राप्त करते हैं। (जो मनुष्य इस) काय्य मार्ग में निरत रहते हैं, उन कामोजनों को सरस्वती, लक्ष्मी, आदिशक्ति गौरी- ब्रह्म (विद्या) रूप धारण करके भलीप्रकार बौध्दिक संसार के महावर्त (भँवर) में डाल देती हैं तथा पंच बाण (पंचेन्द्रियों) और धनुष से विद्ध कर देती हैं (उनका उद्धार कभी नहीं करतीं।

छ: ऐश्वर्यों (समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य) से सम्पन्न चित् शक्ति, भगवान् काम और ईश (कामेश्वर) - दोनों (विद् शक्ति सामान्यात्मा की दृष्टि से) सम प्रधान, समान सत्त्व से युक्त, समान ओज से युक्त (दयार्द्र होकर

निष्काम) उपासक को ब्रह्मपद प्रदान कर देते हैं। उन दोनों (शिव-शक्ति या काम-ईश) के मध्य (तीनों शरीरों से विलक्षण) अजर (जरारहित) यह विश्वमाता (श्री शक्ति) स्थित रहती है। (उपासक की निष्काम) भावना से भावित (ज्ञान, विज्ञान और सम्यक् ज्ञान रूपी) हवि द्वारा भली प्रकार संतुष्ट हुई (आवरण और विक्षेप को), गलाकर नष्ट कर देती है। (इस प्रकार उपासक संसार से) अमनस्क होकर सम्पूर्ण जगत् के विधाता, पालक एवं संहारक (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) बनकर विश्वरूपता को प्राप्त कर लेता है। यह ऋयजु, साम, अथर्व तथा अन्य विद्याएँ (पुराण, न्याय, मीमांसा आदि 14 सैवँलोक्य) वाणीरूप स्तोत्रों से स्तुतियाँ करती हैं। यही त्रिपुरा नाम की महोपनिषद् है। ह्रीं यही चित् और शक्ति तत्त्व है। यही चैतन्य शक्ति तत्त्व है।



विश्व चॉकलेट दिवस

दुनिया भर में आज विश्व चॉकलेट डे मनाया जा रहा है। पहली बार 7 जुलाई 1550 में फ्रांस में चॉकलेट डे मनाया गया, जिसके बाद से पूरी दुनिया चॉकलेट डे को मनाने लगी। चॉकलेट खाना किससे पसंद नहीं है। बच्चों हो या बड़े सभी बड़े चाव से चॉकलेट खाते हैं। चॉकलेट के इतिहास की बात करें तो चॉकलेट का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। चॉकलेट कोको से बनाया जाता है। लोगों का मानना है कि सबसे पहले इसका आविष्कार अमेरिका में हुआ था क्योंकि कोको का पेड़ सबसे पहले अमेरिका के जंगलों में पाया गया था। लेकिन चॉकलेट के इतिहास को समझने के लिए प्राचीन मेसोअमेरिका या वर्तमान मेक्सिको तक जाना पड़ेगा। इस प्रारंभिक विद्यार्ण, जिसकी अक्षय (ज्ञानस्वरूप) परम (सैवँलोक्य) वाणीरूप स्तोत्रों से स्तुतियाँ करती हैं। यही त्रिपुरा नाम की महोपनिषद् है। ह्रीं यही चित् और शक्ति तत्त्व है। यही चैतन्य शक्ति तत्त्व है।

के लिए इसका सेवन किया। सदियों बाद मायावासी भुने हुए और पिसे हुए कोकोआ के बीजों को सिली, पानी और मक्के के आटे में मिलाकर पीते थे और इसे देवताओं का पेय कहते थे। उन्होंने मिश्रण को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला, जिसके परिणामस्वरूप यह एक गाढ़ा और झागदार पेय बन गया जिसे क्कोकोलाल कहा जाता है जिसका अर्थ है कड़वा पानी। इतना ही नहीं चॉकलेट का उपयोग न केवल अनुष्ठान करने और स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए एक पेय के रूप में किया जाता था, बल्कि इसे 15 वीं शताब्दी तक मुद्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। 1528 में स्पेन ने मैक्सिको को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके साथ ही वहां का राजा मैक्सिको से कोको के बीज और सामग्री को भी स्पेन लेकर आ गया। स्पेन के लोगों को कोको इतना पसंद आया कि वहां



के लोगों का ये पसंदीदा पेय बन गया। किंवदंतियाँ हैं कि कोर्टेस को सोने की खोज करते समय अमेरिका में चॉकलेट मिली। अन्वेषक को एज़टेक सम्राट ने सोने के बदले एक कप कोकोआ दिया था। स्पेन में चॉकलेट शहद और चीनी के साथ मिश्रित होने पर अपने

मीठे स्वाद के लिए लोकप्रिय हो गया था। कुछ ही समय में चॉकलेट अमीरों का फैंसी ड्रिंक बन गया। इसे इतना पसंद किया गया कि कैथोलिक भिक्षुओं ने भी इसे धार्मिक प्रथाओं में सहायक माना। स्पेनिश ने चॉकलेट को दुनिया से गुप्त रखा। यह शब्द तब सामने आया जब 1615 में, फ्रांसीसी राजा लुई 13 वें ने ऑस्ट्रिया के ऐनी से शादी की, जो स्पेनिश राजा फिलिप 3 की बेटी थी। रानी फ्रांस के शाही दरबार में चॉकलेट लाई। इसके तुरंत बाद पूरे यूरोप ने भूमध्य रेखा के साथ अपने स्वयं के कोको बगान

स्थापित करना शुरू कर दिया। पूरे यूरोप के राजघरानों ने स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ चॉकलेट का सेवन किया चॉकलेट का इतिहास जारी है क्योंकि यह इलाज यूरोपीय अधिजात वर्ग के बीच बेहद लोकप्रिय रहा। रॉयल्स और उच्च वर्ग ने अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए चॉकलेट का सेवन करते रहे।

आज चॉकलेट हमारे जन्मदिन केक से लेकर मीठे पेय पदार्थों तक सभी समारोहों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। चॉकलेट ने हमारे जीवन और हमारे दिलों को पूरी तरह से भर दिया है। चॉकलेट खाना हर उम्र के लोगों को पसंद होता है। बच्चों लेकर बड़ों तक सभी चॉकलेट खाने को लेकर उत्साहित नजर आते हैं। चॉकलेट को कभी भी खाली खा सकता है और यही कारण है कि इसे हर सेलिब्रेशन में शामिल किया जाता है। डार्क चॉकलेट खाने से शरीर को फायदा भी पहुंचता है। चॉकलेट खाने से स्ट्रेस कम होता है और शरीर की थकावट भी दूर होता है।

शरद पवार ने भी कर दी बाल ठाकरे वाली गलती

संजय तिवारी

महाराष्ट्र की राजनीति में जो गलती बाल ठाकरे ने की, ठीक वही गलती शरद पवार ने भी दोहरा दी। बाल ठाकरे ने जिस शिवसेना को पैदा किया था, जब उसका उत्तराधिकार देने की बारी आयी तो उन्होंने सबसे अयोग्य उत्तराधिकारी को चुना। उद्धव ठाकरे अपने बाकी दो भाइयों के मुकाबले बहुत संकोची और शांत स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं। 1996 में बिन्दूमाधव की मौत और जयदेव की परिवार से दूरी के बाद बाल ठाकरे के नैन नक्श वाले राज ठाकरे ही राजनीतिक मामलों को देखा करते थे। पार्टी और परिवार दोनों ही जगह नकचढ़े राज ठाकरे बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी मान लिये गये थे। लेकिन 1999 में जब बीजेपी-शिवसेना की सरकार चली गयी उसके कुछ सालों बाद ही शिवसेना में उत्तराधिकार का एक अनपेक्षित दावेदार पैदा हो गया। इस दावेदार का नाम था उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने यह दावा क्यों किया ये तो वह जानें, लेकिन उनके दावे की भनक बाल ठाकरे को चुनी तो उन्होंने राज और उद्धव को आपस में बात करके विवाद सुलझाने की सलाह दी। दोनों में बात भी हुई लेकिन विवाद नहीं सुलझा। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि राज ठाकरे पार्टी छोड़ दें नहीं तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाए।

शर्मिले स्वभाव वाले उद्धव का यह जिद्दी स्वभाव देखकर बाल ठाकरे भी हतप्रभ हुए होंगे लेकिन जिनके दो मोटे अब उनके साथ न हों, वह तीसरे बेटे का बात तो पाल ही लेता है। अल्लूत में उद्धव ठाकरे ने उत्तराधिकार का जो दावा किया वह



उनका अपना दावा भी नहीं था। इसके पीछे एक कोटरी थी जिसमें उनकी पत्नी, उनका सहायक और बाद में संजय राउत भी शामिल हो गये थे। इस कोटरी को लगता था कि बाबा बूढ़े हो रहे हैं इसलिए पार्टी की विरासत उद्धव ठाकरे के हाथ में होनी चाहिए। जैसे चालाक लोग मिलकर किसी सीधे व्यक्ति को सामने रख देते हैं और अपनी बात उसके मुंह से कहवाते हैं, वही कुछ उस समय शिवसेना में हुआ। जो चालाक लोगों की कोटरी थी उसे उद्धव जैसा सीधा सरल मुखौटा चाहिए था, ताकि वो परोक्ष रूप से पार्टी चला सकें जिसमें सबसे प्रमुख नाम उनकी अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे का ही था। ठाकरे परिवार में वैसे भी महिलाओं का दबदबा रहा है। बाल ठाकरे की पत्नी मीनाताई ठाकरे जब तक जीवित थीं उनकी बात सबसे ऊपर रहती थी। उनकी असमय मौत के बाद ठाकरे परिवार में जयदेव की पत्नी स्मिता ठाकरे की चल्न लगी। इसलिए रश्मि ठाकरे की अपनी दबी इच्छा रही होगी कि परोक्ष रूप से ही सही पार्टी और ठाकरे परिवार की कमान उन्हें के हाथ में रहनी चाहिए। उद्धव ठाकरे भी न तब विरोध कर पाये और न उस समय जब ठाकरे

परिवार की परंपरा से अलग हटकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार किया गया। वो क्या चाहते थे, ये तो वही जाने लेकिन वे जो कह रहे थे वह उनके अपने ही स्वभाव के विपरीत था।

इसका परिणाम ये हुआ कि शिवसेना खुद बहुमत के साथ ठाकरे परिवार को छोड़कर चली गयी। चली तो उसी दिन जाती जिस दिन बाल ठाकरे का निधन हुआ था क्योंकि शिवसेनिकों को उद्धव में अपना नेता नहीं दिखता था। लेकिन मातोश्री में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थीं जिससे शिवसेना विधायकों को उद्धव से अलग जाने से फिलहाल रोक दिया था। अगर बाल ठाकरे परिवार से अधिक पार्टी की चिंता करते तो उद्धव को कोटरी द्वारा बनाये गये दबाव के आगे कभी न झुकते। उनका वह झुकना ही कालांतर में शिवसेना के टूटने तथा मातोश्री के महत्व के कम हो जाने का कारण बन गया। अब एनसीपी के शरद पवार ने भी ठीक वही गलती दोहराई है जो बाल ठाकरे दो दशक पहले कर चुके थे। अजित पवार को वही सुप्रिया सुले भी एनसीपी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानती हैं जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर शरद पवार ने अजित पवार को किनारे करने का संकेत दिया। शरद पवार का अपना कोई बेटा नहीं है। यह शरद पवार के लिए हो सकता है कोई अधिक महत्व की बात न हो। लेकिन उनकी पत्नी और बेटे के लिए अजीत पवार उसी कमी को पूरा करे थे। पहली बार अजीत पवार ने जब विद्रोह किया था तब शरद पवार की पत्नी के समझाने पर ही वो वापस लौटे थे। वो काका से राजनीतिक विद्रोह तो कर सकते थे लेकिन आई (माई) की बात नहीं टाल सकते थे इसलिए वो वापस लौट भी

आये। उन्हें उम्मीद रही होगी कि काका के बाद पार्टी का काम काज उन्हें ही संभालना है। वो पार्टी को उसी हैसियत में चलाते भी थे। एक दो नेताओं को छोड़ दें तो पार्टी के अधिकांश नेता/विधायक भी उनके साथ वैसे ही जुड़े हुए थे। लेकिन सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के साथ शरद पवार ने बाल ठाकरे की तरह संकेत दे दिया कि उन्हें बेटा उद्धव ठाकरे मंजूर है परंतु भतीजे राज को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनायेंगे। बाल ठाकरे वाली यही सोच शरद पवार को भी भारी पड़ गयी। अब शरद पवार पार्टी बचाने के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं उससे दोनों के बीच दूरियां और बढ़ेंगी। जो लोग यह मानते हैं कि शरद पवार ने जानबूझकर ऐसा हो जाने दिया ये उनका अपना आकलन हो सकता है लेकिन सच्चाई संभवतः इससे उलट है। ये उत्तराधिकार की लड़ाई है जिसमें शरद पवार ने मुंहबोले बेटे की बजाय बेटे का पक्ष लिया यह जानते हुए कि बेटे शायद पार्टी को उस तरह से न चला सके जैसे वो चलाते आये हैं। लेकिन जानते तो बाल ठाकरे भरे थे। शिवाजी मैदान से कहा था कि लोग मेरे उत्तराधिकारी में मेरे जैसे नैन नक्श तलाशते हैं। लेकिन इससे जरूरी तो नहीं कि नये तरह के लोगों को नेतृत्व न दिया जाए। इसलिए शरद पवार से अजित पवार का अलगाव उत्क्राव की ओर जाएगा। इसका संकेत सुप्रिया सुले के उस बयान से भी मिलता है जिसमें उन्होंने कहा है कि वास्तविक एनसीपी शरद पवार के साथ है और हम लोग उसके असली नेता हैं। इस टकराव में जो बचेगा वही महाराष्ट्र की राजनीति में आगे बढ़ेगा।

बापू की दिनचर्या

भेंट-वार्ता (भाग-2)



गतांक से आगे...

ब्रजकृष्णजी चाँदीवाला के शब्दों में मुलाकातियों के बीच बापू की मार्मिक झाँकी यहाँ प्रस्तुत है। मुलाकात के समय बापू इतने विभिन्न विषयों पर बातें करते कि चर्चित रह जाना पड़ता। अभी वे आकाश की बातें करते तो दूसरे क्षण पाताल की बातें करने लग जाते। अभी वे गवर्नर जनरल से भारत के भविष्य की बातें करके ही आए कि इससे उनके सामने अपने घर के झगड़े छेड़ दिए। पति-पत्नी की नहीं बनती, विवाह किसका किससे हो, घर का खर्च कैसे चले व्यापार कौन-सा हो आदि बातें तक उनका मुलाकातों में होतीं। सरदार पटेल और नेहरुजी अभी हुकूमत संबंधी बातें करके गए ही कि ताड़ का गुड़ कैसे बना, चावल कौन-सा खाना चाहिए, सब्जी और फल के क्या गुण हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से क्या लाभ हैं, इन विषयों पर बात छिड़ गई। कोई राजदूत अभी अपने देश की बातें करके गया कि वैज्ञानिक ने विज्ञान की बातें शुरू कर दीं। कभी तारों की बातें चल पड़तीं तो कभी एटम बम की, कभी लड़ाई की, तो कभी अध्यात्म की। मतलब यह कि मुलाकातों के विषय इतने भिन्न होते और बापू हर विषय पर इतनी सरलता और जानकारी के साथ बातें करते कि सुननेवाले के मन में अनायास यह प्रश्न उठ खड़ा होता कि क्या वे कोई विश्वकोश हैं, जो सभी बातों का पता रखते हैं? बापू की याददाश्त कमाल की थी। हम क्षण भर पहले की बात भूल जाते हैं, मगर उन्हें पचास वर्ष पहले की घटना याद रहती, जैसे बात भूल चुके हुई हो। हजारों व्यक्ति उनसे मिलने आते, लेकिन वे एक बार जिसका चेहरा देख लेते, उसका नाम उन्हें सदा के लिए याद हो जाता। यदि कोई उनकी कही किसी बात का गलत हवाला देने लगता तो वे तुरंत उसकी भूल पकड़ लेते। बापू की समय की कटोर पाबंदी छोटे-बड़े सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती। वे स्वयं निश्चित समय पर तैयार हो जाते। यदि कताई या चल रहा अन्य कार्य पहले पूरा हो जाता और मुलाकातियों को दिए गए समय में दस-पाँच मिनट की भी गुंजाइश होती तो वे अभी समय है, जरा सो लूँ- यह कहकर शरीर पर पड़ी चादर आढ़कर तुरंत सो जाते और निश्चित समय से आध मिनट पूर्व जाग जाते।

कैबिनेट में अहम फैसला, पांच प्रतिशत बढ़ा सरकारी कर्मचारियों का डीए

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों के डीए में पांच फीसदी की वृद्धि की गई है। सीएम हाउस में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टवीट कर इसकी जानकारी दी। कर्मचारियों के हड़ताल के बीच सीएम का ये एलान काफी अहम माना जा रहा है। दूसरी ओर वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर 6 जुलाई को दोपहर 2.30 बजे शंकर नगर स्थित अपने शासकीय निवास कार्यालय में कैबिनेट मीटिंग का ब्रीफिंग की।

सीएम ने टवीट कर लिखा कि आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए.) में पांच प्रतिशत की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इससे पूर्व निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक शुरू होने के पहले सीएम भूपेश ने उप मुख्यमंत्री महाराज साहब टी.एस. सिंदेदेव जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।

कैबिनेट की बैठक में 29 बिंदुओं का फैसला

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते (डी.ए.) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। शासकीय कर्मचारियों को एक और सौगात देते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है साथ ही स्वेचिक्क सेवा नियुक्ति हेतु अर्हतादायी सेवा की अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया है।

प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 के उपस्थापना हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के



प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के रिक 3722 एवं सहायक शिक्षकों के 5577 पद भरने के लिए भर्ती नियम को शिथिल करते हुए स्वीकृत सेटअप में विषयवार पदों की भर्ती की बाधिता को हटाए जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य शासन द्वारा आम लोगों को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराने बाजार मूल्य गाईडलाईन दरों को 30 प्रतिशत घटाया गया है। जिसको प्रभावशीलता 31 मार्च 2023 तक थी। इस छूट को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री जी की बेमेतरा जिले की ग्राम पंचायत संबलपुर, महासमुंद्र जिले की ग्राम पंचायत भंवरपुर तथा राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा के परिपालन में आबादी के निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति में उन्नयन हेतु औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन करते हुए इसमें महिला उद्यमिता नीति 2023 को समावेशित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमिit भूमि का व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एवं रियायती स्थायी पट्टों को भूमिस्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया।

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अन्वयोदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों को शक्कर वितरण हेतु अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक आवश्यक शक्कर की मात्रा राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से क्रय करने का निर्णय लिया गया। शक्कर का क्रय मूल्य 33,000 रुपए प्रति टन निर्धारित किया गया।

खनिज साधन विभाग में मानचित्रकार, अनुरोधक एवं खनिज सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची की 01 वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैधता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।

वन विभाग में विभागीय सेटअप स्वीकृत दिनांक 26 मार्च 2003 के बाद से नियुक्त किए गए समस्त वन रक्षकों का वेतनमान 3050-4590 मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के डिप्टी कलेक्टर, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान से संयुक्त कलेक्टर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में वर्ष 2017 बैच तथा विचारक्षेत्र में आने वाले लगभग 18 राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों को पूर्व की भांति रिक वरिष्ठ पदों के विरुद्ध वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के संयुक्त कलेक्टर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान अपर कलेक्टर, प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नत क्रमोन्नत हेतु 10 वर्ष सेवा अवधि में 6 माह की छूट देते हुए वर्ष 2014 बैच के पात्र

अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2023 का अनुमोदन किया गया।

टाटा टेक्नालाजीस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में हुए एम.ओ.यू. की शर्तों के संबंध में निर्णय लिया गया।

वरिष्ठ समाजसेवी श्री प्रभुदत्त खेरा द्वारा संचालित अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपरवा विकासखण्ड लोरमी वर्तमान में अभ्यारण्य शिक्षक समिति द्वारा संचालित है, यहां पूर्व से कार्यरत 07 कर्मचारियों को इस स्कूल के लिये स्वीकृत सेटअप में समायोजन कर संविलियन करने का निर्णय लिया गया।

ग्राम बिरनपुर, तहसील - साजा, जिला बेमेतरा में दिनांक 08 / 04 / 2023 को घटित घटना में मृतक श्री साहू के परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

विश्व बैंक एवं आईफेड से बाह्य सहायता प्राप्त चिराग परियोजना अंतर्गत त्रिपथीय अनुबंध तथा परियोजना कार्यान्वयन योजना के अनुसारा परियोजना संचालन प्रक्रियाओं के संबंध में निर्णय लिया गया।

बीवीएससी स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण सहा.प.चि.क्षे. अधिकारी (तृतीय श्रेणी) से पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (राजपत्रित द्वितीय श्रेणी) संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित आठ प्रतिशत को केवल एक बार के लिये छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

आवेदक रायपुर राज देवांगन कल्याण समाज रायपुर

के सामाजिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु ग्राम रायपुरा में आबंटित शासकीय भूमि की निर्धारित प्रव्याजि राशि में छूट देने का निर्णय लिया गया।

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के सैन्य छावनी की स्थापना के लिए ग्राम चकरभाटा, विलासपुर में कुल रकबा 1012.48 एकड़ भूमि को समर्पित कर भुगतान की गई मुआवजा राशि को वापस करने का निर्णय लिया गया।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

केन्द्रीय मोटर यान (24वां संशोधन) नियम, 2021 अंतर्गत 51क मोटर वाहन कर में रियायत लागू करते हुये छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में उद्युत अनुसूची जोड़ने एवं पुराने वाहनों के स्क्रेपिंग के संबंध में निर्णय लिया गया।

खाद्य निरीक्षकों की भर्ती 2022 हेतु मेरिट सूची की वैधता अवधि में 06 माह की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति, 2022 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

आरडीएसएस योजना की अनिवार्यता के तहत शासकीय विभागों के बकाया विद्युत देयकों के भुगतान हेतु राज्य शासन द्वारा ट्रांसमिशन कंपनी के आर. ई. सी. लिमिटेड एवं पी.एफ.सी. लिमिटेड के त्रया की राशि का टेक ओवर किए जाने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार ऋय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1999 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

संक्षिप्त समाचार

मरकाम आज धमतीरी में बूथ चलो अभियान में होंगे शामिल

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम

07 जुलाई शुक्रवार को सुबह 6 बजे कोण्डागांव से धमतीरी के लिये रवाना होंगे। सुबह 10 बजे कोसमरा में बूथ चलो अभियान में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे ग्राम बागदेही में बूथ चलो अभियान में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे ग्राम कोलियारी में बूथ चलो अभियान में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे ग्राम नवागांव में बूथ चलो अभियान में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे ग्राम भैंसबोड में बूथ चलो अभियान में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे ग्राम भैंसबोड से रायपुर के लिये रवाना होंगे।

पट्टु बिनने जंगल गाए वृद्ध पर हाथी ने किया हमला, मौत

जशपुर। बादल खोल वनाभरण में हाथी के हमले से एक वृद्ध की मौत हो गई है। पट्टु बिनने जंगल गया था वृद्ध, जिस पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के कुचलने से वृद्ध की मौके पर मौत हो गई। मृतक सुभाष यादव 60 वर्ष सुबह 5 बजे जंगल गया था इस दौरान हाथी ने उसे मौत के घाट उतार दिया।

विस सेन्ट्रल हॉल में श्यामा प्रसाद को जयंती पर किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधान सभा परिसर स्थित सेन्ट्रल हॉल में प्रतिष्ठापित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैल चित्र पर आज उनकी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिव दिनेश शर्मा ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर विधान सभा परिसर स्थित प्रेक्षागृह के मुख्य द्वार पर स्थापित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की गयी। इस अवसर पर विधान सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनको स्मरण किया।

राशन दुकान से 26 बोरी चावल, 2 बोरी शक्कर और नगदी 5 हजार पार

रायपुर। विधानसभा इलाके के ग्राम धनसुली में स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान से अज्ञात चोर ने दुकान की खिड़की तोड़कर 26 बोरी चावल, 2 बोरी शक्कर और नगदी 5 हजार रुपये चंपत हो गया। दुकान संचालक की रिपोर्ट पर विधानसभा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राकेश कुमार जांगड़े जो कि ग्राम धुरकोनी में रहता है और ग्राम धनसुली में उसकी शासकीय उचित मूल्य की दुकान है जहां कुछ दिन पहले ही राशन का सामान चावल, शक्कर और नमक की खेप वितरण के लिए दुकान में रखा था जिससे रोज ग्राहकों को वितरण किया जाता था। रोजाना की तरह गुरुवार को राकेश सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान में ही रहता था। जिसके बाद वह दुकान में ताला लगाकर रोज की तरह अपने घर चला जाता था। इसी बीच 24 जून की रात में कोई अज्ञात चोर दुकान की खिड़की तोड़कर अंदर रखा 26 बोरी चावल, 2 बोरी शक्कर और 5 हजार नगदी की चोरी कर ले चंपत हो गया। इसकी जानकारी राकेश को दुकान में राशन वितरण के दौरान बोरियों की गिनती करने पर पता चला। जिस पर पड़ताल करने पर पता चला कि दुकान के पीछे की दीवार की खिड़की टूटा हुआ था और दुकान के गोदाम में रखा सामान कम था। इस पर उभरने थाना जाकर दुकान में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।

प्रदेश शराब घोटाले में 2,161 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ : ईडी

वरिष्ठ नौकरशाहों, राजनेताओं और उनके सहयोगियों के सिडिकेट ने दिया शराब घोटाले को अंजाम

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में 2,161 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है, जो 2019 में सूबे के वरिष्ठ नौकरशाहों, राजनेताओं, उनके सहयोगियों और उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों की मिली भगत का परिणाम है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रायपुर की विशेष अदालत के समक्ष बीते मंगलवार को दायर अपनी अभियोजन शिकायत में कहा कि शराब बिक्री से हासिल की गई जिस 2,161 करोड़ रुपये की धनराशि को राज्य के खजाने में जानी चाहिए थी। वह भ्रष्ट नेताओं, अफसरों और अन्य आरोपियों के जेब में गई।

ईडी ने इस केस में कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर एजाज देबर के भाई अनवर देबर, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के प्रबंध निदेशक अरुणपति त्रिपाठी, शराब व्यवसायी त्रिलोक सिंह दिल्ली, होटल व्यवसायी नितेश पुरोहित और अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट में ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि 13,000 पत्रों के दस्तावेजों को आधार बनाते हुए जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह अभियोजन शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अदालत में दायर कर रही है।

ईडी ने अपनी शिकायत में कहा कि जांच से पता चला है कि राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग में 2019 से 2023 के बीच कई तरीकों से अभूतपूर्व



भ्रष्टाचार किया गया था और इसमें शामिल सिडिकेट द्वारा लगभग 2,161 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया। जिस राज्य के खजाने में जाना चाहिए था और उससे केंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजस्व प्राप्त होना चाहिए था।

ईडी का दावा है कि जिस उत्पाद शुल्क विभाग की मुख्य जिम्मेदारियों में शराब की आपूर्ति को विनियमित करना, जहरीली शराब की त्रासदियों को रोकने के लिए गुणवत्तापूर्ण शराब सुनिश्चित करना और राज्य के लिए राजस्व अर्जित करना था लेकिन हाल ही में रिटायर हुए आईएसएस अधिकारी अनिल टुटेजा और अनवर देबर की अनुवाद में अपारधिक सिडिकेट ने इसके ठीक उल्टा किया और बड़े पैमाने पर शराब भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह, राजनेता, उनके सहयोगी और उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों ने एक सिडिकेट बनाकर शराब नीति को अपनी इच्छा से बदला और उसके जरिये अधिकतम व्यक्तित्व लाभ उठाया।

फरवरी 2019 में भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी को इस कारण से सीएसएमसीएल (शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय) का प्रमुख बनाया गया ताकि शराब सिडिकेट भ्रष्टाचार को अंजाम दे सके। उस

साल मई में देबर के आदेश पर अरुणपति त्रिपाठी उन्हें को प्रबंध निदेशक बनाया गया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि त्रिपाठी को सीएसएमसीएल द्वारा खरीदी गई शराब पर एकत्रित रिश्वत कमीशन को अधिकतम करने और सीएसएमसीएल द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब की बिक्री के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का काम सौंपा गया था।

इस साजिश के तहत सीएसएमसीएल के एमडी केवल पसंदीदा निर्माताओं से शराब खरीदते थे और जो कमीशन नहीं देते थे, उन्हें दूकानार कर देते थे। एजेंसी ने आरोप लगाया कि ईडी को दिए गए बयानों के अनुसार अनवर देबर शराब से मिले कमीशन को इकट्ठा करते थे और उसमें से बड़ा हिस्सा सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ साझा करता था। सिडिकेट ने सीएसएमसीएल द्वारा संचालित दुकानों के माध्यम से बेहिसाब अवैध शराब के निर्माण और बिक्री को साजिश रची। ईडी ने कहा कि साजिश के हिस्से के रूप में सिडिकेट द्वारा डिस्टिलर्स को डुप्लिकेट होलोग्राम प्रदान किए गए थे और डिस्टिलर्स द्वारा डुप्लिकेट बोतलें नकद में खरीदी गई थीं।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि डिस्टिलर, ट्रांसपोर्ट, होलोग्राम-निर्माता, बोतल-निर्माता, उत्पाद शुल्क अधिकारी, उत्पाद शुल्क विभाग के उच्च अधिकारी, देबर, वरिष्ठ आईएसएस अधिकारी और राजनेता सहित सभी को बाकायदा उसका हिस्सा दिया जाता था। अभियोजन पक्ष की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए देबर और दिल्ली के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि उनके मुक्किलों को मामले में जूटा फंसाया जा रहा है।

मोदी के बैनर-पोस्टर से पटा शहर

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। पीएम मोदी रायपुर में करीब दो घंटे रहेंगे, इस दौरान प्रदेशभर से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा पीएम मोदी के चेहरे और काम के दम पर मैदान में उतरेगी। स्वागत में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। विमानतल से लेकर साइंस कालेज मैदान तक जिस प्रकार बैनर पोस्टर होर्डिंग्स व झंडे लगे हैं पूरा माहौल मोदीमय नजर आ रहा है। हर छोटे बड़े नेता ने अपने स्तर पर बैनर पोस्टर लगाये हैं, सड़कों पर भी भाजपा के झंडे से सजावट की गई है। पीएम मोदी के स्वागत ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से साइंस कालेज मैदान में पोस्टर और बैनर से पाट दिया गया है। पूरे शहर में पीएम मोदी का चेहरा नजर आ रहा है। भाजपा नेताओं ने विशेष रणनीति के तहत पोस्टर अभियान चलाया है, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र है।

मुस्लिम समाज के नेताओं ने किया भाजपा प्रवेश, मोदी की सभा में होंगे शामिल

दुर्ग। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की नई-नई उपलब्धियों से नवाजे जाने से प्रभावित होकर दुर्ग शहर के तकिया पारा वार्ड के मुस्लिम समाज के सदस्य बड़ी संख्या में जिला भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और लोकसभा सांसद विजय बघेल की उपस्थिति में भाजपा प्रवेश किया। मुस्लिम समाज के सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश दिलाया। भाजपा प्रवेश करने वाले सभी मुस्लिम समाज के नेता 7 जुलाई को आगामी 7 जुलाई को रायपुर में होने वाली



नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होंगे। भाजपा प्रवेश के बाद मुस्लिम समाज के सदस्यों ने आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फतेह दिलाने का वादा किया और आगामी 7 जुलाई को रायपुर में होने वाली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा में शरीक होने और दुर्ग से अधिक से अधिक मुस्लिम समाज के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में रायपुर जाने का न्योता देने का भरोसा दिलाया। भाजपा प्रवेश करने वाले मुस्लिम

समाज के सदस्यों में असलम नाथानी, शेख फारुख चौधरी, बाबर खान, जुबेर भाई, हाजी मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद इम्तियाज उर्फ चुन्नू भाई, मोहम्मद भाई, मोहम्मद शहीद गोलू, मोहम्मद नफीस,

मोहम्मद अनीस, शेख मोहम्मद रफीक, मंटू भाई, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद अशफाक शामिल थे।

इसी दौरान लोकसभा सांसद विजय बघेल ने भाजपा में शामिल हुए मुस्लिम समाज के सदस्यों से सौजन्य भेंट कर उनके उज्वल जीवन के लिए शुभकामनाएं प्रदान की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बह रही विकास की धारा बिना किसी भेदभाव के समाज के हर तबके तक पहुंच रही है जिसका फायदा निश्चित रूप से मुस्लिम समाज के बंधुओं को भी बड़ी संख्या में मिल रहा है।

अमित शाह ने रायपुर में भाजपा नेताओं के साथ किया चुनाव प्लान पर मंथन

छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने थामी चुनावी कमान

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी पारा चढ़ चुका है। चुनावी बिसात में राजनीतिक दलों ने जोर आजमाया शुरू कर दी है। 2018 से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। लिहाजा बीजेपी सत्ता में कम बैक करने की जुगत में लगी हुई है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा हुआ है। रायपुर पहुंचने के बाद अमित शाह सीधे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। यहां अमित शाह के नेतृत्व में प्रदेश बीजेपी की बैठक में चुनावी प्लान पर चर्चा हुई। अमित शाह ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का भी जायजा लिया।

शाह कांग्रेस के किले को भेदने की बना रहे रणनीति- 90 विधानसभा सीटों और 11 लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी की तरफ से अमित शाह चुनावी रणनीति को तैयार करने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पटखनी देने के लिए अमित शाह ने छत्तीसगढ़ बीजेपी



के नेताओं से वन टू वन की। अमित शाह को चुनावी रणनीति का मास्टर माना जाता है। यही वजह है कि शाह ने लगातार छत्तीसगढ़ को दो बार दौरा कर यहां बीजेपी नेताओं को चुनावी मंत्र दिया। कुशाभाऊ परिसर में अमित शाह की बैठक देर रात तक चली। बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माधुर, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, नितिन नबीन, अरुण साव, अजय जामवाल मौजूद रहे। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर खाका तैयार किया गया। साथ ही पीएम

मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर भी चर्चा की गई।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने बताया कि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कैसे चुनाव लड़ना है। कैसे जीतना है, इसको लेकर सार्थक चर्चा हुई है। वही संगठन में फेरबदल के सवाल पर धरमलाल कौशिक ने कहा कि अभी किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर भी धरम लाल कौशिक ने कहा कि इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। शाह गुरुवार सुबह 10.45 बजे दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत की। स्थानीय नेताओं के साथ शाह की बैठक चुनावी रणनीति तैयार करने में काफी अहम साबित होगी।

मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से नए चेहरों को मिल सकती है जगह- खबरों के मुताबिक अमित शाह

को इस मीटिंग में मोदी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं से चर्चा हो सकती है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक पार्टी फोरम से नहीं हुई है।

छत्तीसगढ़ का मौजूदा सियासी समीकरण- छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। जबकि विधानसभा की 90 सीटें हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। चुनाव के बाद कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी। बीजेपी को 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा। जेसीसीजे और बीएसएम को कुल मिलाकर सात सीटें मिली थी। बाद में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने तीन सीटें जीतीं। उसकी संख्या 71 पहुंच गई। बीजेपी की सीटें 14 हो गईं। अब दुर्ग से विधायक विद्यारतन भसीन के निधन के बाद बीजेपी की सीटें 13 हो गईं हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के पास तीन और बहुजन समाजवादी पार्टी के पास 2 सीटें हैं। वर्तमान में 1 सीट खाली है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। जबकि कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं।

एमएस में क्रिटिकल केयर यूनिट का लोकार्पण

बनेगा क्रिटिकल केयर ब्लॉक, एक ही स्थान पर गंभीर रोगियों को मिलेंगी सभी सुविधाएँ

रायपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला रखी। लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से बने वाले 150 बेड के इस ब्लॉक में अति गंभीर रोगियों को एक ही स्थान पर सभी चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त होंगी। इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली को दुनिया की श्रेष्ठ चिकित्सा प्रणाली बताते हुए कहा कि अब चिकित्सकों को डेटा कंपाइलेशन और मेटा डेटा के ऊपर शोध कर स्वयं में आत्मविश्वास का एक नया स्तर प्राप्त करना होगा।



कोशिश की जा रही है। एमएस के चिकित्सा शिक्षकों के साथ संवाद में उन्होंने कहा कि मंत्रालय प्रयास कर रहा है कि स्थापित एमएस के वरिष्ठ चिकित्सक अन्य एमएस में कुछ माह के लिए शिक्षण कार्य के लिए जाएँ। उन्होंने कहा कि भारत में चिकित्सा एक पेशा नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना जाता है। कोविड काल में

चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टॉफ ने भारत के इस सेवा मॉडल को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर एक नया गौरव हासिल किया है। उन्होंने कहा कि एमएस ने चिकित्सा सेवाओं के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं जिसे आगे ले जाने की आवश्यकता है। डॉ. मांडविया ने चिकित्सा शिक्षकों का आह्वान किया कि वे शोध और नवोन्मेष की ओर ध्यान

केंद्रित करें। भारतीय चिकित्सक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, इस आत्मविश्वास के साथ वे दुनिया को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। छात्रों के साथ एक अन्य संवाद कार्यक्रम में उन्होंने नोट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर पनप रही आशंकाओं का जवाब देते हुए कहा कि मंत्रालय का प्रयास है कि छात्रों को

प्रतिस्पर्द्धी माहौल प्रदान किया जा सके जिससे वे देश के साथ विदेश में भी अपने सेवाएँ प्रदान कर सकें। उन्होंने कहा कि आठ साल में मंत्रालय ने चिकित्सा शिक्षा की सीट्स दो गुना कर दी हैं। अगले तीन वर्ष में स्नातक के अनुरूप पर-स्नातक की सीट्स कर दी जाएंगी। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ ही नर्सिंग छात्रों के पाठ्यक्रम में विदेशी भाषाएँ भी सम्मिलित करने की योजना है। उन्होंने कोविड काल में किए गए प्रयासों को भारत की समर्थ गाथा बताया और कहा कि यह सभी के सम्मिलित प्रयत्न का पराकाष्ठा थी। शीघ्र ही उनकी एक किताब इस विषय पर आ रही है।

इस अवसर पर सांसद (रायपुर) श्री सुनील सोनी और सांसद (राज्यसभा) सुश्री सरोज पांडेय भी उपस्थित थीं। निदेशक प्रो. (डॉ.) नितिन एम. नागरकर ने बताया कि नए ब्लॉक में 150 बेड्स, आईसीयू, एड्युटीवू, जांच सुविधाएँ और सीटी स्कैन जैसी सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इसे कोविड जैसी महामारी के साथ पृथक रूप से भी प्रयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नए ब्लॉक से प्रदेश के रोगियों को काफी लाभ मिलेगा।

पीएम मोदी-सीएम बघेल एक साथ मंच करेंगे साझा

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजधानी रायपुर में शुक्रवार को 7600 करोड़ की 10 परियोजनाओं की सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहली बार रायपुर पहुंच रहे पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी और सीएम बघेल स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से हेलीकाप्टर से साइंस कालेज मैदान पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री बघेल पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पीएम के साथ नजर आएंगे।



पीएम मोदी के कार्यक्रम में पांच केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ-साथ पांच केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. मनसुख मांडविया, रेल मंत्री अश्विनि वैष्णव, केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं

भाजपा नेताओं ने सभा की तैयारियों का लिया जायजा

पीएम मोदी साइंस कालेज मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस सभा में डेढ़ लाख लोगों की भीड़ जुटने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी की सुबह 10.45 बजे सभा को देखते हुए बस्तर से लेकर सरगुजा के कार्यकर्ता गुरुवार रात को ही राजधानी पहुंच गए हैं। साइंस कालेज मैदान में आयोजित विजय संकल्प रैली की तैयारी का जायजा लेने प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित अन्य नेता पहुंचे।

मोदी के बैनर-पोस्टर से पटा शहर

विमानतल से साइंस कालेज मैदान तक हुआ मोदीमय

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। पीएम मोदी रायपुर में करीब दो घंटे रहेंगे, इस दौरान प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा पीएम मोदी के चेहरे और काम के दम पर मैदान में उतरेगी। स्वागत में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। विमानतल से लेकर साइंस कालेज मैदान तक जिस प्रकार बैनर पोस्टर होर्डिंस व झंडे लगे हैं पूरा माहौल मोदीमय नजर आ रहा है। हर छोटे बड़े नेता ने अपने स्तर पर बैनर पोस्टर लगाये हैं। सड़कों पर भी भाजपा के झंडे से सजावट की गई है।



नेताओं ने विशेष रणनीति के तहत पोस्टर अभियान चलाया है, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र है। देश का गौरव बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट को पोस्टर में शामिल किया गया है। सभा की तैयारी के लिए भाजपा नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है।

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री प्रदेश की जनता को साधेंगे। पिछले नौ वर्ष में उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता

के सामने रखेंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि इस सभा को विजय संकल्प जनसभा नाम दिया गया है। यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सात और आठ जुलाई को दो दिन के भीतर प्रधानमंत्री चार राज्यों के पांच शहरों में दौरा करेंगे। इनमें रायपुर (छत्तीसगढ़), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), वाराणसी (तेलंगाना), बीकानेर (राजस्थान) शामिल हैं।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल में आमजन को निम्न सामग्री ले जाना प्रतिबंधित

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पीएम की सुरक्षा में जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जा रही है। रायपुर में होने वाले पीएम के आमसभा की सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। वहीं अब रायपुर पुलिस ने कार्यक्रम स्थल में जाने वाले सभी आम जनता के लिए प्रतिबंधित चीजों की लिस्ट की पोस्टर जारी की है। इस पोस्टर में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रायपुर प्रवास के दौरान कार्यक्रम स्थल साइंस कालेज मैदान सरस्वती नगर रायपुर में आम सभा को सम्बोधित किया जाएगा।

इसलिए कार्यक्रम स्थल में आमजन को अपने साथ निम्न सामग्री ले जाना प्रतिबंधित है। आम सभा में प्रतिबंधित वस्तुएं ऐसे सामान न लेकर जाएं। बोड़ी, सिराटे, तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला इत्यादि। माचिस, लाइट, लेजर लाइट, इत्यादि अर्गन सामग्री। चाकू, कैची, कटर, नेलकटर, पिन, ऑलपिन, पेचकस, पल्ला एवं अन्य कोई भी धारदार वस्तुएं। पानी का बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स बोतल, कैन, समस्त प्रकार के बोतलबंद पेय पदार्थ एवं ज्वलनशील सामग्री।

पीएम मोदी के आगमन पूर्व भाजपा की बाइक रैली

राजधानी हुई भाजपा मय, बाइक रैली निकालकर मोदी जी की सभा का प्रचार

रायपुर। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन हेतु भाजपा हर प्रकार की तैयारियों में जुट गई है। रायपुर के साइंस कालेज मैदान में मोदीजी की बड़ी आमसभा होने जा रही है जिसमें 2 लाख लोगों के आमसभा में पहुंचने का अंदाजा है। ऐसे में भाजपा हर प्रकार की तैयारियों में सुस्तीदी से काम कर रही है। भाजपा नेताओं द्वारा प्रभात फेरी निकाल कर, निमंत्रण पत्र के माध्यम से और शहर की सड़कों और गलियों में प्रचार गड्डियां घुमा कर प्रचार किया गया।

इसी कड़ी में रायपुर शहर में एक भव्य बाइक रैली आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बाइक में सवार होकर शहर भर के मुख्य मार्गों से गुजरे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन पूर्व शहर में आमसभा हेतु माहौल तैयार किया गया।



गुरुवार की दोपहर पं.दीनदयाल गुरुवार आडिटरियम से एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। हजारों मोटरसाइकल में युवाओं का हुजूम अपने नेता के प्रति उसाह और समर्पण को इंगित करता है। बाइक रैली के पूर्व मोडिया से मुखातिब हुए राजेश मृगत ने कहा की नरेन्द्र मोदी की वैश्विक लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है भारत में रहने वाला हर वर्ग का नागरिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपना नेतृत्वकर्ता मानता है और इसी का प्रमाण है की यहां आज हजारों की संख्या में युवा स्वतः आज यहां बाइक रैली में अपना योगदान देने पहुंचे हैं नरेन्द्र मोदी ने केंद्र में अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में इतने जनहितैषी कार्य करें हैं की उससे हर वर्ग प्रभावित हुआ है और अपने प्रधानमंत्री के प्रति स्नेह और कृतज्ञता का भाव रखता है देश विदेश में मोदी का डंका बज रहा है। उन्हे प्राप्त वैश्विक सम्मान से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। श्री मृगत ने रायपुर शहर और प्रदेश की जनता से अपील करता हूँ की अपने प्रधानमंत्री के स्वागत हेतु अधिक से अधिक संख्या में तैयार साइंस कालेज मैदान पहुंचे।

टमाटर, अदरक के बाद अब बीस बरबटी ने भी दिखाए अपने तेवर

रायपुर। शतक और अर्धशतक अभी तक यह शब्द से क्रिकेट में सुनने को मिलता था लेकिन अब यह शब्द सब्जियों में कॉमन हो चुका है। दरअसल इन दिनों सब्जियों के दाम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं स्थिति यह है कि कई सब्जियों के दाम शतक लगा चुके हैं तो कुछ के दाम अर्धशतक तक पहुंच चुके हैं। मसलन यह कि कई सब्जियों के दाम 7100 किलो या उससे अधिक हो गए हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल पा रही है। खराब मौसम के चलते लगातार सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंच रहा है जिसके कारण सब्जियों की आवक बेहद कम हो गई है। आवक कम होने डिमांड अधिक होने के कारण सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं अभी तक सिर्फ टमाटर ही 7100 किलो सुपर बिक रहा था लेकिन अब शिमला मिर्च, हरी मिर्चस धनिया पत्ती, बीस, बरबटी यह सब्जियों के दाम भी लगभग 7100 किलो पहुंच गए हैं। इसके अलावा कई और सब्जियों के दाम 750 से अधिक हो गए हैं। सब्जियों के दाम अधिक होने का असर यह हो रहा है कि सब्जी लेने महिलाओं के बजाए पुरुष बाहर निकल रहे हैं ताकि वह अपने बजट के हिसाब से सब्जी की खरीदी कर सकें।

पीएम मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस के 21 सवाल

रायपुर। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। दूसरी बार पीएम बनने के बाद उनका ये पहला दौरा होगा क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए केवल 4 महीने का ही वक बचा है इसलिए पीएम के दौरे को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर प्रदेश और देश के कुल 21 मुद्दों पर सवाल पूछे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को ओर से पूछे गये सवालों को प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जारी किया उन्होंने कहा 9 साल का रिकार्ड है प्रधानमंत्री मोदी जी सवालों के उत्तर तो नहीं देते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से हम प्रधानमंत्री से इन सवालों को पूछना चाहते हैं। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था लेकिन 3285 दिन में भी महंगाई कम क्यों नहीं हुई? 7 नवंबर 2013 को कांकर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता से वादा किया था कि सभी के खाते में 15 लाख आंयेंगे? 15-15 लाख रुपया जनता के खाते में कब आंयेंगे? 3 9 साल में विदेश से कितना कालाधन वापस आया? दो करोड़ रोजगार प्रतिबंध के वादानुसार 18 करोड़ रोजगार युवाओं को कब मिलेगा? 5 किसानों की आमदनी दुगुनी कब होगी? उपज की कीमत लागत मूल्य से डेढ़ गुना कब मिलेगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क़रूड आंयल के दाम घट गये है फिर भी देश में पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस के दाम कम क्यों नहीं हो रहे है? उज्ज्वला के हितग्राहियों के सिलेंडर कब भरेंगे? 8 9 साल में देश के ऊपर कर्जभार 150 लाख करोड़ कैसे बढ़ गया?

विस चुनाव : शाह ने नेताओं को दिए महत्वपूर्ण सुझाव

रायपुर। भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश भाजपा के नेताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं। उन्होंने संगठन पदाधिकारियों की बैठक लेकर आगे की रणनीति तय कर दी है। वहीं चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियों को लेकर भी उन्होंने समीक्षा की है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल देर रात तक भाजपा नेताओं की अलग-अलग बैठक ली है। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, धरमलाल कौशिक, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, नितिन नवीन, अरुण साव, अजय जमवाल आदि शामिल थे। भाजपा नेताओं के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई है। कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे जीतना है, इसको लेकर सार्थक चर्चा हुई है। संगठन में फेरबदल के सवाल पर बताया गया कि अभी किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वहीं चुनाव समिति घोषणा पत्र समिति को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। श्री शाह ने भाजपा नेताओं को विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर अपना महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया है। इसके अलावा उन्होंने संगठनात्मक समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों के प्रदर्शन आदि भी और बेहतर बनाने, कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए बूट करने जैसे सुझाव दिया है।

बड़े किसान आंदोलन की तैयारी, 32 संगठनों की हुई बैठक

रायपुर। चुनावी वर्ष में राज्य में बड़े किसान आंदोलन की तैयारी चल रही है। आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए आज रायपुर में संयुक्त किसान मोर्चा की की बैठक हुई। मंडल प्रवीन स्योकद, नंदकुमार विशाल और सौर यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ में विभिन्न जनांदोलनों का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किए गए इनमें बस्तर संभाग में चल रहे 24 अनिश्चितकालीन धरना, हसदेव को बचाने आंदोलन, गेल पाइपलाइन प्रभावित किसानों का आंदोलन आदि शामिल हैं। बैठक में आगामी तीन सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन रायपुर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 15 से 25 सितंबर के बीच संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी संगठनों द्वारा यात्राएं करने का निर्णय लिया गया। सभी यात्राएं 25 सितंबर को रायपुर में पहुंचेंगी जहां तीन दिन का महा धरना / महापड़व/ किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में समन्वयन समिति से जुड़े संगठनों बीच समन्वय करने और मीटिंग में हुए कार्यक्रम को लागू करने के लिए नौ सदस्यीय समन्वयन समिति का गठन किया गया। इसमें अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा, छत्तीसगढ़ किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय किसान संघ बालोद, जिला किसान संघ राजनादांगव, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन शामिल हैं।

गृहमंत्री अमित शाह को डॉ. रमनसिंह ने पेंशनरों के हित में धारा 49 को हटाने पत्र सौंपा

रायपुर। गृहमंत्री अमित शाह के 5 व 6 जुलाई 23 को प्रवास में रायपुर आगमन पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमनसिंह ने उन्हें पत्र देकर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों के आर्थिक स्वत्वों के भुगतान में बाधक बनी मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को विलोपित करने का आग्रह किया। डॉ रमन सिंह ने अपने पत्र में अवगत कराया है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के अनुसार मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के पेंशनरों के स्वत्वों का 74 प्रतिशत 26 प्रतिशत व्यय वहन करना है जिसमें 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी की जमींदारी छत्तीसगढ़ शासन का है। जिसके लिए दोनों राज्यों में परस्पर सहमति आवश्यक है जबकि धारा 49(6) में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। उन्होंने आगे बताया है कि भारत सरकार द्वारा दोनों राज्यों के मुख्यसचिव को प्रेषित पत्र दिनांक 13/11/17 के अनुसार पेंशन दायित्व के लिए उत्तरवर्ती राज्यों को पारस्परिक सहमति की आवश्यकता नहीं है फिर भी धारा 49(6) के आधार पर राशि के बहाने दोनों राज्यों के द्वारा पेंशनर्स को राशि रोक रखा गया है फलस्वरूप 6 लाख पेंशनर केन्द्र से 9? प्रतिशत पीछे है। अतः प्रस्ताव अनुसार अधिनियम की उक्त धारा को विलोपित करने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करने बाबत सम्बन्धित को निर्देशित किये जाने का आग्रह किया है।

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए सिंहदेव

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव राज्य के पहले डिप्टी सीएम बनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में दिल्ली में हुई बैठक के बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का आदेश जारी हुआ है। सिंहदेव (70 वर्ष) 2018 के चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष थे और चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इन्कम्बेन्सी के साथ घोषणा पत्र को भी काफी अहम माना जाता है. टीएस सिंहदेव के पिता स्व. एमएस सिंहदेव अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं, वहीं उनकी मां देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मंत्री रह चुकी हैं। डिप्टी सीएम के पेलान के बाद सिंहदेव ने कहा, आलाकमान ने जो जिम्मेदारी दी है, उसे ईमानदारी से पूरा करेंगे. सरगुजा से निकलकर छत्तीसगढ़ की सेवा का

अवसर मिला है. सबको साथ लेकर बेहतर तालमेल से काम करेंगे. इलाहाबाद में जन्म 70 वर्षीय टीएस सिंहदेव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट से अम्बिकापुर से विधायक चुने गए हैं। यह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 10 कहलाता है, जो अनारक्षित सीट है। उनके पिता का नाम महाराजा स्व. एम.एस. सिंहदेव हैं। टीएस सिंहदेव का जन्म 31 अक्टूबर 1952 को इलाहाबाद, जिला - इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी अभिरूचि पढ़ाई, खेल, यात्रा, वन्यजीव पर्यावरण में है। उन्हें अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अम्बिकापुर (दो बार) रहते हुए पुरस्कार मिला है। उनकी विशेष उपलब्धियों में चैयरेमन, राज्य वित्त आयोग रहना है। उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, स्विटजरलैंड, इटली,

आस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, मलेशिया, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस, दुबई, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका (सभी निजी यात्राएं) की विदेश यात्राएं की हैं। सार्वजनिक एवं राजनैतिक जीवन सन 1983 में राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले टीएस सिंहदेव सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, अंबिकापुर संयोजक, यूथ कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ व अध्यक्ष, जिला सेवा दल रहे। 2003 में अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग बने। इस दौरान उन्हें कॅबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। टीएस सिंहदेव अंबिकापुर सीट से प्रथम बार 2008 में विधायक निर्वाचित हुए। उसके उपरांत 2013 फिर जीत कर आये। इस दौरान वे नेता प्रतिपक्ष रहे। 2018 में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की टिकट से विधायक

चुने गए। 2018 में ही वे प्रदेश सरकार में मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, योजना एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी 20 सूत्रीय एवं वाणिज्य कर (जी.एस.टी.)। सदस्य, कार्य मंत्रणा समिति छत्तीसगढ़ विधानसभा बने। अंबिकापुर विधानसभा में कुल मतदाता 226012 हैं। जिनमें से 178749 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यहां मतदान का प्रतिशत 79.09 फीसदी रहा। टीएस सिंहदेव को 100439 (56.19 फीसदी) वोट प्राप्त हुए थे। जबकि उनके खिलाफ मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंहदेव को 60815 (34.02 फीसदी) प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे।

राज्यपाल से उपमुख्यमंत्री ने की भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव ने सौजन्य भेंट की और राज्य से जुड़े विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव ने सौजन्य भेंट की और राज्य से जुड़े विषयों पर चर्चा की।